विजय मत

राष्ट्र को समर्पित

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

www.vijaymat.com | भोपाल, शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 | वर्ष- 11 | अंक- 80 | पेज- 08 | मूल्य- ₹5.00/-

ज्ञानामृत

मानव का मानव होना ही
उसकी जीत है, दानव होना हार है, और
महामानव होना चमत्कार है।
▶▶डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

अब इस्राइल में भी चलेगा भारत का यूपीआई... पीएम नेतन्याहू संग संयुक्त प्रेसवार्ता में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

'टाइम टेस्टेड साझेदारी' को स्पेशल स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप पर ले जाने का निर्णय

यरुशलम, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप' का दर्जा देने की घोषणा की। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-इस्राइल रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं और अब इन्हें नई दिशा व तेज गति देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सहयोग साझा समृद्धि का इंजन बन चुका है। पिछले वर्ष हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते के बाद अब मुक्त व्यापार समझौते को भी जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। तकनीक को भविष्य की साझेदारी का केंद्र बताते हुए उन्होंने एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। इस्राइल में यूपीआई के इस्तेमाल पर भी सहमति बनी है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त विकास, उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और अंतरिक्ष में भी सहयोग विस्तारित होगा।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शांति पर सहमति

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलों को गति देने और संवाद के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती और साझा आकांक्षाओं का प्रतीक है।

मोदी-नेतन्याहू वार्ता में हुए प्रमुख फैसले

- **रक्षा और रणनीतिक सहयोग:** सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति।
- **मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए):** पारस्परिक लाभ वाले एफटीए को आगे बढ़ाने पर जोर।
- **यूपीआई कनेक्टिविटी:** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और इस्राइल की मसाव के बीच यूपीआई प्रणाली जोड़ने पर सहमति।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई):** शिक्षा और उभरती तकनीकों में एआई सहयोग हेतु अलग समझौता।
- **साइबर सुरक्षा:** साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर।
- **मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर:** तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति।
- **कृषि नवाचार:** 'इंडिया-इस्राइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर' स्थापित करने का निर्णय।
- **भू-भौतिकीय अन्वेषण:** ऊर्जा और संसाधन खोज के क्षेत्र में साझेदारी।
- **लोथल समुद्री धरोहर परिसर:** विकास में सहयोग का समझौता।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- **व्यापार और सेवाएं:** वाणिज्य, विनिर्माण और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यान्वयन प्रोटोकॉल तय।

वित्तीय सहयोग: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण और इस्राइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी के बीच समझौता।

सीईओ फोरम: चौथे भारत-इस्राइल सीईओ फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत।

NCERT किताब पर सुप्रीम सख्ती

'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर बैन, छपी किताबें जब्त करने और डिजिटल कॉपी हटाने का आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सोशल साइंस की पुस्तक में शामिल 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक वाले अध्याय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने किताब के छपाई और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि जो प्रतियां पहले ही छप चुकी हैं, उन्हें जब्त किया जाए और डिजिटल संस्करण भी तुरंत हटाए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे उन्हें गहरा दुख है और अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। साथ ही अध्याय तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के शिक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि पुस्तक चाहे स्कूलों में उपलब्ध हो, स्टॉक में हो या ऑनलाइन, उसे तत्काल प्रभाव से पहुंच से हटाया जाए। आदेश का उल्लंघन जानबूझकर अवमानना माना जाएगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत एक समिति गठित कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराएगी।

न्यूज इन शॉर्ट

भरोसे, सत्यापन और निष्पक्ष रेवेन्यू मॉडल पर बनें ठोस नीतियां: वैष्णव

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के प्रमुख प्रकाशक समूहों की डिजिटल इकाइयों के संगठन डीएनपीए द्वारा आयोजित डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026 में डिजिटल युग में समाचार माध्यमों की भूमिका पर व्यापक विमर्श हुआ। कार्यक्रम में

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक मीडिया जगत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और भविष्य की नीतियों के लिए सामूहिक सहमति व ठोस सिफारिशें आवश्यक हैं। मंत्री ने कहा कि मानव समाज भरोसे की संस्थाओं पर टिका है–परिवार से लेकर न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया तक। मीडिया संस्थानों की निष्पक्षता और जिम्मेदारी ही उनकी विश्वसनीयता की आधारशिला है। उन्होंने चेताया कि डीप फेक, भ्रामक सूचनाएं और सिंथेटिक कंटेंट जैसी चुनौतियां लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं।

डीजीसीए: टिकट बुकिंग के 48 घंटे में रद्द करने पर पूरा रिफंड

नई दिल्ली, एजेंसी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई टिकट रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में अहम बदलाव करते हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के तहत अब टिकट बुक करने के

48 घंटे के भीतर उसे रद्द करने या उसमें बदलाव करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और पूरा भुगतान वापस किया जाएगा। यह सुविधा तब लागू होगी जब टिकट उड़ान की तारीख से कम से कम सात दिन पहले बुक किया गया हो। नए प्रावधानों के अनुसार यदि टिकट ट्रेवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक किया गया है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। एयरलाइंस को हर हाल में 14 कार्यदिवस के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि 48 घंटे की 'फ्री लुक-इन' अवधि समाप्त हो जाती है, तो सामान्य कैंसिलेशन नीति लागू होगी और निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा।

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर 15 दिन की रोक

कोच्चि, एजेंसी। केरल हाई कोर्ट ने बहुचर्चित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड' की प्रस्तावित रिलीज पर 15 दिनों के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म

सर्टिफिकेशन ने प्रमाणपत्र जारी करते समय अपेक्षित सावधानी नहीं बरती। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि फिल्म में केरल की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

गजल

सतेन्द्र सत्यज

वो दगाबाज होकर भला हो गया!
पूछता है बताओ तो क्या हो गया!!

जब से टूटा है दिल तब से पत्थर हुआ,
ज़ख्म ही आख़िरी में दवा हो गया!

हमने तारीफ़ की उसको अच्छी लगी,
हमने सच क्या कहा वो खफ़ा हो गया।

सर झुकाकर नमन है हमारा उन्हें,
जो भी धरती पे अपनी फ़िदा हो गया!

उसकी नज़रों में सत्यज नहीं देखना,
जिन पे पूरा शहर ही फ़िदा हो गया!!

भीलवाड़ा में 'इन्वेस्ट इन एमपी' पहल का आयोजन... निवेशकों से बोले मुख्यमंत्री मोहन...

मप्र अनंत संभावनाओं का अनुपम केंद्र निवेश हर मायने में फायदे का सौदा

विजय मत, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है और यहां निवेश हर मायने में फायदे का सौदा है। भीलवाड़ा में आयोजित 'इन्टरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एमपी' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि वे देश के दिल से जुड़ें और विकास व अवसरों के केंद्र का हिस्सा बनें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश व्यापार, उद्योग स्थापना और निर्यात के लिए रणनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उद्योग-अनुकूल नीतियां, मजबूत अधोसंरचना और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों के लिए आदर्श वातावरण तैयार कर रहे हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश को 'अनंत संभावनाओं का अनुपम केंद्र' बताते हुए राजस्थान के निवेशकों का स्वागत किया और कहा कि दोनों राज्यों के बीच साझा संस्कृति और व्यापारिक संबंधों का इतिहास रहा है।

मध्यप्रदेश भी बढ़ते हुए राजस्थान के साथ करेगा अपनी भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ के उद्योगपतियों की व्यापारिक कुशलता अद्वितीय है। पद्म विभूषण स्वर्गीय घनश्याम दास बिड़ला द्वारा नागदा में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज की स्थापना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह दोनों राज्यों के ऐतिहासिक औद्योगिक संबंधों का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना पर हुए समझौते से दोनों राज्यों को जल उपलब्धता की नई सौगात मिली है। यूरोप के साथ टेक्सटाइल व्यापार में भी व्यापक संभावनाएं हैं।

बड़े निवेश प्रस्तावों पर विशेष रियायत... डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने स्वयं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाली है ताकि निवेश संबंधी प्रक्रियाएं सरल और त्वरित हों। राज्य में 18 नई उद्योग-अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं। बड़े निवेश प्रस्तावों पर विशेष रियायतें दी जा रही हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र में देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क मध्यप्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने मेवाड़ के निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया।

निवेशकों के लिए सशक्त आधार... मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और ग्रीन एनर्जी उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विस्तृत लैंड बैंक, पर्याप्त जल संसाधन, कुशल मानव संसाधन और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी निवेश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों की सराहना की और सीमावर्ती जिलों में नए टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क की मांग रखी।

मंत्रालय में छापामार जांच के निर्देश

लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, जनहित कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई: मोहन

विजय मत, भोपाल

राज्य मंत्रालय में कार्यसंस्कृति को दुरुस्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वल्लभ भवन में छापामार जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग को आदेशित किया है कि गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन स्थित सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन किया जाए। इस दौरान आने-जाने का समय तथा अनधिकृत अनुपस्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड संकलित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष टीमों का गठन कर उन्हें संबंधित कार्यालयों में तैनात कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी आदेश की जानकारी दे दी गई है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब मंत्रालय स्तर पर समय पालन को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। डॉ. मोहन यादव पहले भी अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने की हिदायत दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पांच दिवसीय कार्यप्रणाली लागू होने के बावजूद कई अधिकारी निर्धारित समय का पालन नहीं करते, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है और आम नागरिकों के प्रकरण लंबित रहते हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि समयबद्ध उपस्थिति से ही योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्णय प्रक्रिया में गति लाई जा सकती है।

नागौर के निजी स्कूल में दर्दनाक घटना

खेलते समय गिरी 9 साल की छात्रा, हार्ट अटैक से मौत

नागौर (राजस्थान), एजेंसी

नागौर जिले के गोटन कस्बे स्थित गोटन इंटरनेशनल स्कूल में 23 फरवरी की सुबह नौ वर्षीय छात्रा की कथित हृदयाघात से मौत हो गई। छात्रा दिव्या, जो पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी, प्रार्थना से पहले स्कूल मैदान में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी।

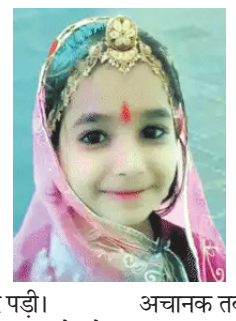

स्कूल स्टाफ ने तत्काल परिजनों को सूचना दी और उसे गोटन के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले और प्रारंभिक तौर पर कार्डियक अरेस्ट को मौत का कारण माना गया है। परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया। परिवार ने बताया कि दिव्या के बड़े भाई अभिषेक की भी चार माह पहले इसी तरह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। लगातार दो बच्चों की असामयिक मौत से परिवार सदमे में है और क्षेत्र में चिंता का माहौल है।

केंद्र सरकार सख्त... 28 फरवरी के बाद बिना सिम नहीं चलेंगे मैसेजिंग एप

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 'सिम बाइंडिंग' नियम लागू करने की 28 फरवरी की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नए नियमों के तहत मोबाइल फोन में सक्रिय सिम कार्ड न होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग एप

काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन व्हाट्सएप भी छह घंटे के भीतर स्वतः लॉगआउट हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से साइबर धोखाधड़ी करने वालों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मंत्री ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को लेकर भी सुरक्षा मानकों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

सेवाधाम आश्रम में बच्चों की मौत, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

डेढ़ माह में 11 बच्चों की मौत, मुख्य सचिव सहित अधिकारियों को नोटिस जारी किए

विजय मत, ब्यूरो उज्जैन/जबलपुर

उज्जैन के अंबोदिया स्थित अंकित सेवाधाम आश्रम में 20 नवंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 के बीच डेढ़ माह में 11 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों में अधिकांश 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बहु-दिव्यांग बच्चे थे। सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई। बीते एक वर्ष में कुल 17 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया है। मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, कलेक्टर उज्जैन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा आश्रम अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने आश्रम की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

पोस्टमॉर्टम और मेडिकल रिकॉर्ड

शासकीय चरक अस्पताल के अनुसार दिसंबर 2025 में आठ और जनवरी 2026 में दो बच्चों की मौत दर्ज की गई। सभी का पोस्टमॉर्टम थाना भैरवगढ़ पुलिस की मौजूदगी में किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अधिकांश बच्चों में एनीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण पाए गए।

आश्रम में कई बच्चों की हालत गंभीर

आश्रम में वर्तमान में करीब 250 निराश्रित और दिव्यांग बच्चे रह रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। संचालक का कहना है कि मृत बच्चे पहले से गंभीर रूप से बीमार थे। इंदौर के एक अन्य आश्रम से 86 बच्चों को यहां शिफ्ट किया गया था, जिनमें से कई मृतकों में शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।

अन्नदाता देश की नींव, आज वही असुरक्षित महसूस कर रहे: राहुल

कन्नूर (केरल), एजेंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। पेरावूर में किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब किसानों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तथाकथित एपस्टीन फाइलों का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया ताकि ऐसा समझौता कराया जा सके जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन

देश की कृषि नींव को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना था कि भारतीय किसान छोटे और सीमित संसाधनों वाले हैं, जबकि अमेरिकी कृषि बड़े पैमाने और उच्च मशीनीकरण पर आधारित है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में खुली पहुंच देना किसानों के हितों के विपरीत होगा। राहुल गांधी ने कहा कि यदि नींव को सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी तो विकास की इमारत टिक नहीं सकती। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किसानों के कारण संभव हुई, लेकिन आज वही वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि कृषि मतभेदों के कारण समझौता महीनों से अटका था और इस दौरान दबाव बनाया गया।

राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव 2026 का गरिमामय समापन

राज्यपाल मंगू भाई पटेल और कुशाभाऊ ठाकरे न्यास के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कार्यक्रम के साक्षी बने

विजय मत खेल संवाददाता, भोपाल

राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव 2026@100 बेहद माहौल में समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल रहे। जबकि अध्यक्षता कुशाभाऊ ठाकरे न्यास के अध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा की गई।

राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन मंडल के मुख्य कर्ताधर्ता डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा एवं सभी संगठन और पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को भी बधाई दी तथा उनका उत्साह बढ़ाया। यह आयोजन आत्म सम्मान और आत्मनिर्भरता का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि वे इस बेहद रोमांचक मैच को प्रत्यक्ष ना देख पाए। मंगू भाई पटेल ने विकलांगों को दिव्यांग संबोधन से सम्मानित किए

जाने पर उनके प्रति कृतज्ञता जताई। खंडेलवाल ने इस आयोजन के मुख्य कर्ताधर्ता डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के प्रयासों के लिए मुक्त कंठ से सराहना की। लगातार बिना रुके बिना थके 100 घंटे तक चले मैच को लेकर आश्चर्य भी व्यक्ति किया। अपने दिव्यांग खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि पूरा समाज आपके साथ है। साथ ही डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से उम्मीद जताई कि वे भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा द्वारा स्वागत भाषण के माध्यम से किया गया। अपने संक्षेप में लगातार 100 घंटे तक चले इस खेल महोत्सव का पूरा लेखा जोखा भी रखा। उन्होंने बताया कि कुल 754 दिव्यांग खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लिया, जबकि 100 महिला खिलाड़ी भी शामिल रहीं। 7 दिव्यांग महिला ओलंपियन खिलाड़ियों की विशेष मौजूदगी रही। उन्होंने बेहद गौरव के साथ यह उल्लेख किया कि इस पूरे आयोजन को स्वर्गीय कुशा भाऊ ठाकरे की स्मृति में आयोजित किया गया। व्हीलचेयर खिलाड़ी शैलेंद्र यादव एवं प्रियेश कुमार ने मंच के आग्रह पर अपने अनुभव साझा किये।

प्रधान संपादक- विजय शुक्ला। कार्यालय: भोपाल ■ शहडोल ■ रायपुर ■ इंदौर ■ जबलपुर ■ होशंगाबाद ■ विदिशा ■ सीहोर ■ बैतूल ■ छिंदवाड़ा ■ ग्वालियर ■ ब्यौहारी ■ अनूपपुर ■ उमरिया ■ सीधी ■ सिंगरौली ■ रीवा ■ सतना ■ मैहर ■ खरगोन ■ बालाघाट ■ सिवनी ■ कटनी ■ सागर ■ मुलताई ■ मुरैना ■ टीकमगढ़

न्यूज इन शॉर्ट

संभाग स्तरीय आजीविका होली मेला का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी को

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन में रंगो के त्यौहार रंगोत्सव में आमजन को शुद्ध एवं देशी पकवान के साथ ही हर्बल गुलाल एवं पूजन सामग्री की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से दो दिवसीय आजीविका होली मेला का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी को पुराना बस स्टैंड के सामने सिंघानिया परिसर शहडोल में किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक होली मेला में स्व सहायता समूह की दीदियो द्वारा निर्मित शुद्ध एवं देशी उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे।

जिला परियोजना समन्वयक श्री अजय सिंह ने बताया कि होली के रंग आजीविका के संग के माध्यम से संभाग स्तरीय आजीविका होली मेले में स्व-सहायता समूहो एवं स्थानीय शिल्पियो द्वारा तैयार उत्पाद के विक्रय से मेक इन इंडिया एवं व्होकल फॉर लोकल अभियान को गति मिलेगी तथा समूह की दीदियो को भी स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। मेले में प्रमुख रूप से हर्बल गुलाल, गौकाष्ट, गोबर के कंडे, पूजन सामग्री, खोवा, गुजिया नमकीन, चिप्स, पापड़ मिठाइयां, बतासे, महुआ के लड्डू एवं बिस्किट, कोदो से बने बिस्किट, कम्पोस्ट खाद, जैविक कीटनाशक, हल्दी मसालें, सुगंधित चावल एवं कपडे के बने बैग मेले के आकर्षण होंगे।

नगरवासियो से अपील की गई है कि होली के त्यौहार में शुद्ध एवं देशी सामग्री का उपयोग कर स्वास्थ्य को सेहतमंद बनाएं तथा स्व सहायता समूह की दीदियो द्वारा निर्मित उत्पादो को प्रोत्साहित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति ने कहा कि यह मेला स्व सहायता समूह की महिलाओ को संबल देने एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया प्रयास है।

शादी की शहनाई के साथ फलों के दाम चढ़े, बाजार में बढ़ी हलचल

शहडोल जिले में शादी-विवाह का सीजन शुरू होते ही फल बाजार में रौनक के साथ कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया है। करीब एक पखवाड़े पहले तक सामान्य दरों पर बिक रहे फल अब ऊंचे दामों पर पहुंच गए हैं। वैवाहिक आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों में फलों की बढ़ती खपत ने बाजार में मांग का दबाव बढ़ा दिया है। सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है और थोक मंडियों से लेकर फुटकर बाजार तक दामों में अंतर साफ नजर आ रहा है।

बता दें कि सेव, जो पहले 80 से 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब 140 से 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। अनार के दाम भी 80-100 रुपए से बढ़कर 140 से 180 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। केला पहले 30 से 50 रुपए दर्जन बिक रहा था, अब 50 से 80 रुपए दर्जन तक पहुंच गया है। तरबूज 40-50 रुपए से बढ़कर 60-70 रुपए प्रति किलो और नाशपाती 50 रुपए से बढ़कर 60-70 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बड़े आयोजनों के लिए थोक में खरीदारी करने वाले परिवारों का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है।

अनूपपुर में हवाई अड्डा निर्माण का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

विधायक एवं पूर्व मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब और कहा मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी प्रगति नहीं दिखाई देती

विजय मत, शहडोल/ अनूपपुर

जिला मुख्यालय अनूपपुर में हवाई अड्डा (एयरपोर्ट) निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग एक बार फिर मध्यप्रदेश विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाई गई। अनूपपुर के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने 25 फरवरी 2026 को बजट सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न क्रमांक 1219 के माध्यम से सरकार से विस्तृत जानकारी मांगते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त 2024 को की गई घोषणा के बाद अब तक क्या ठोस प्रगति हुई है और कार्य प्रारंभ करने की वास्तविक स्थिति क्या है।

विधायक बिसाहू लाल सिंह ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अनूपपुर में हवाई पट्टी/हवाई अड्डा निर्माण हेतु परीक्षण कराए जाने की घोषणा की थी। डेढ़ वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट किया कि क्या स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या आवश्यकता, उपयोगिता एवं व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) परीक्षण कराया गया है और यदि कराया गया है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

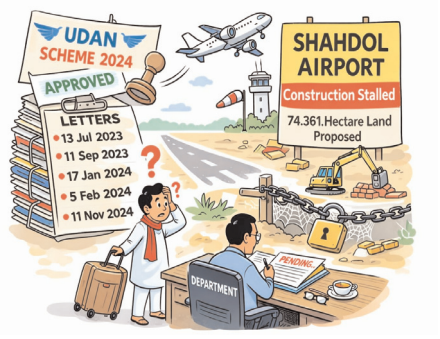

उन्होंने पूर्व में दिए गए लिखित उत्तर का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षण की प्रक्रिया की बात कही गई थी, परंतु अब तक उसके परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। विधायक ने यह भी पूछा कि क्या अनूपपुर को उन जिलों की सूची में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है जहां नई हवाई पट्टी विकसित की जानी है।

सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि ÷मध्यप्रदेश नगर विमानन नीति 2025÷ के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम एक हवाई पट्टी विकसित करने की कार्ययोजना बनाई गई है। इस संबंध में जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर संभावित स्थलों की पहचान, भूमि की उपलब्धता, आवश्यकता एवं व्यवहार्यता परीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर में यह भी स्वीकार किया गया कि वर्तमान में अनूपपुर जिले में कोई हवाई पट्टी निर्मित नहीं है, किंतु प्रारंभिक स्तर पर फिजिबिलिटी सर्वे की कार्यवाही की गई है।

सूत्रों के अनुसार अनूपपुर में कदमटोला क्षेत्र के पास प्रारंभिक सर्वेक्षण कर भूमि चिन्हित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसे संभावित स्थल चयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि अंतिम स्वीकृति सर्वे रिपोर्ट और तकनीकी परीक्षण के बाद ही मिल पाएगी, लेकिन प्रारंभिक भूमि चिन्हांकन से जिले में उम्मीद जगी है कि परियोजना आगे बढ़ सकती है।

विधायक एवं पूर्व मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि अनूपपुर संभागीय दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर्यटन, खनिज संपदा, धार्मिक स्थल और औद्योगिक संभावनाएं मौजूद हैं। हवाई अड्डा बनने से न केवल निवेश और पर्यटन को गति मिलेगी, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, प्रशासनिक गतिविधियों और व्यापारिक संपर्कों में भी तेजी आएगी।

उन्होंने अपने कार्यकाल में जिले के विकास के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति, नर्मदा लोक जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। विधायक सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य अनूपपुर को विकास की मुख्यधारा में लाना है और वे भविष्य में भी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

क्षेत्र में उनके समर्थक और आमजन उन्हें ÷विकास पुरुष÷ के रूप में भी संबोधित करते हैं, जो जिले के समग्र विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद जिले की जनता की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अंतिम स्वीकृति कब देती है और हवाई अड्डा निर्माण का कार्य कब धरातल पर शुरू होता है। विधायक बिसाहू लाल सिंह की पहल से यह स्पष्ट है कि वे अनूपपुर के विकास को लेकर गंभीर हैं और इस परियोजना को मूर्त रूप दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने उठाया 13 गायों की मौत का मामला , रिपोर्ट पर सस्पेंस

सीसी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग से गरमाई राजनीति

विजय मत, धनपुरी

धनपुरी क्षेत्र के अमलाई ओसीएम में 29 जनवरी 2026 को हुई 13 गायों की संदिग्ध मौत का मामला अब प्रशासनिक जांच से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। घटना के लगभग एक महीने बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक न होने पर सवाल तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल धनपुरी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने थाना प्रभारी धनपुरी को पत्र क्रमांक 27, दिनांक 24 फरवरी 2026 के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर दोनों दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि घटना के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों का परीक्षण किया था, लेकिन अब तक विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे क्षेत्र में तरह-तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। उस समय स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी रही कि कथित रूप से कोलरी क्षेत्र से निकले बॉइलर के पानी को पीने से गायों की मौत हुई। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है।

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक ट्रक दिखाई देने की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा फुटेज को कब्जे में लेने की जानकारी दी गई, लेकिन उस आधार पर क्या कार्रवाई हुई, यह स्पष्ट नहीं किया गया। ज्ञापन में दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है, साथ ही उस समय ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी बात कही गई है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भी आक्रोश देखा गया था। गौवंश से जुड़ा मामला होने के कारण इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा अहम माना जा रहा है,।

अधिकारी क्या पत्रकारों को विज्ञापन का पेमेंट अपने वेतन से करते हैं ?

विजय मत, शहडोल

इन दोनों तमाम विभागों के अधिकारी पत्रकारों को यह बोलकर टरका रहे हैं कि विज्ञापन का पेमेंट वेतन मिल जाने पर करेंगे। यह आश्चर्य की बात है कि गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के विज्ञापनों का भुगतान करने में आला अधिकारी इस तरह की बहाने बाजी कर रहे हैं । इसलिए सवाल उठता है कि क्या जिले से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया अर्थात क्या ऊपरी कमाई अधिकारियों को नहीं हो रही है या फिर ऊपरी कमाई हो तो रही है परंतु अधिकारी यह समझ रहे हैं कि पत्रकारों को कुछ नहीं मालूम है । दरअसल कोई अधिकारी विज्ञापनों का पेमेंट अपनी जेब से नहीं करता है या अपनी वेतन से नहीं देता है बल्कि भ्रष्टाचार के कमीशन से मिली राशि के माध्यम से हमेशा भुगतान होता रहा है, यह परंपरागत रूप से वर्षों से चला आ रहा है । यह बात अलग है कि पहले पत्रकारों की यह समाचार पत्रों की संख्या कम थी, आजकल ज्यादा हो गई है परंतु यह भी सच है कि पहले की अपेक्षा भ्रष्टाचार भी चरम पर है । अधिकारी गले तक भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं परंतु विज्ञापन के भुगतान करने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इस खबर के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को विजयमत का संदेश है कि आप पत्रकारों को झूठ बोलकर बेवकूफ न बनाए क्यों कि यह बात सभी मीडियाकर्मी जानते हैं कि कौन अधिकारी काली कमाई किस शहर में और कहां खफा रहा है साथ ही अपने बच्चों को कहां-कहां देश विदेश में पढ़ाने के लिए भेजता है। यह भी पत्रकारो को जानकारी हैं कि अधिकारियों की चल अंचल संपत्ति कहां-कहां कितनी- कितनी है। यदि पत्रकार अपनी औकात पर आ जाए तो भ्रष्ट अधिकारी की कुंडली खोलकर रख सकता है।

कई महीनो से बंद आरो महाप्रबंधक के निर्देश के बाद फिर हुआ शुरू

विजय मत, धनपुरी

धनपुरी फिल्टर प्लांट सोहागपुर क्षेत्र जलप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और आसपास का क्षेत्र शुद्ध पेयजल के लिए फ़िल्टर प्लान्ट पर निर्भर करता है। फिल्टर प्लांट में थोड़ी सी समस्या लोगों की समस्या बन जाती है। विगत 4 वर्षों से फिल्टर प्लांट में बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जलप्रदाय का कार्य चल रहा था लेकिन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अचानक सबमर्सिबल पंप 100 एचपी के दो, फेल हो गए जिसके कारण जलप्रदाये संकट उत्पन्न हो गया। फिल्टर प्लांट में उसे समय 100 एचपी के तीन पंप चल रहे थे और उस पंप के करण विभिन्न क्षेत्र जैसे अमरा डंडी, स्टोर कॉलोनी अमलाई,चार नंबर, तीन नंबर, एक नंबर,जीएम ऑफिस,चिकित्सालय, गेस्ट हाउस आरसी कॉलोनी रेलवे कॉलोनी छोटी अमलाई,उसलापुर को जलप्रदाये किया जाता था।

अचानक दो पंप के फेल हो जाने से पानी का भीषण संकट उत्पन्न हो गया और जहां पानी

सप्लाई प्रतिदिन किया जाता था, वहीं कई क्षेत्रों में यह पानी एक दिन छोड़ कर दिया जाने लगा।

समस्या को गंभीरता के देखते हुए महाप्रबंधक सोहागपुर बी के जेना के द्वारा पंप को तत्काल रिपेयरिंग करने और अन्य स्रोतों से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

क्षेत्रीय कार्यशाला के प्रभारी डॉक्टर?म ए अच सिद्दीकी और इंजीनियर अजय द्विवेदी के निरंतर प्रयास से स्थिति में काबू पाया गया और वर्तमान में पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया गया,और पानी वितरण प्रति दिन सुचारू रूप से चलने लगा।

वर्तमान में एकीकृत जलप्रदाय योजना फिल्टर प्लांट सोहागपुर में,पांच पंप चल रहे हैं जिसमें 100 एचपी के तीन, 40 एचपी का एक, और 30 एचपी का एक पंप चल रहा है। और इन सब पंप ओं को रखरखाव बनाए रखने के लिए फिल्टर प्लांट के फोरमैन राम केर,सचिन जायसवाल बीजू समुल आदि दिन-रात लगे रहते हैं।

आवश्यक श्रम शक्ति का बेहद अभाव -

फिल्टर पॉइंट में एक समय डेढ़ सौ से ज्यादा श्रम शक्ति हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में एक दर्जन के लगभग बची है और ठेकेदारी श्रमिकों के सहयोग के साथ यह प्लांट चल रहा है लेकिन मूलभूत समस्या अभी भी बनी हुई है।फिल्टर पॉइंट में पंप ऑपरेटर,फिटर, फिटर हेल्पर का बेहद अभाव है जिसके कारण प्रतिदिन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। फ़िल्टर प्लांट से लगभग 10 किलोमीटर की पाइपलाइन का रखरखाव और पांच सबमर्सिबल पंप और 7 सप्लाई पंप के रखरखाव की समस्त जवाबदारी

मांग पूरी नहीं हुई तो हिंद मजदूर सभा आरकेटीसी कंपनी के खिलाफ आंदोलन की होगी मजबूर

धनपुरी एसईसीएल सोहागपुर एरिया के अमलाई ओपन कास्ट में प्राइवेट कंपनी आरकेटीसी के खिलाफ हिंद मजदूर सभा आंदोलन को लेकर तैयारी तेज कर दी है पिछले दिनों ही सोहागपुर एरिया हिंद मजदूर सभा के द्वारा एरिया महाप्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रबंधक अमलाई ओपन कास्ट को ज्ञापन देकर आरकेटीसी कंपनी के द्वारा जो आठ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था उन्हें फिर से बहाल करने की मांग की गई थी और एक सप्ताह के अंदर अगर कंपनी सभी बर्खास्त आठ ठेका कर्मचारियों को बहस नहीं करती तो हिंद मजदूर सभा चका जाम और वृहद आंदोलन करने को मजबूर होगी और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो समय सीमा हिंद मजदूर सभा के द्वारा दी गई थी वह पूरी होने को है और अभी तक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बर्खास्त 8 ठेका कर्मचारी को बहाल करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर अब हिंद मजदूर सभा चुप नहीं बैठेगी और कोयला डिस्पैच खदान के गेट बंद करने को लेकर मजबूर होगी। इन मजदूर सभा के एरिया अध्यक्ष राकेशकांत पांडे एवं महामंत्री नीरज चतुर्वेदी ने बताया कि अमलाई ओपन कास्ट में विगत दिनों आरकेटीसी कंपनी के द्वारा हिंद मजदूर सभा ठेका कर्मचारी संघ के आठ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और यही कारण है कि लगातार चर्चा करने के बाद भी कंपनी के द्वारा अभी तक सभी बर्खास्त आज ठेका कर्मचारियों की बहाली नहीं की गई है और यही कारण है कि अब हिंद मजदूर सभा आंदोलन को मजबूर होगी इसके पहले ही संगठन के द्वारा एरिया महाप्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया था

बदलते मौसम की मार जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा

शहडोल जिले में इन दिनों मौसम के लगातार बदलते तेवर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। सुबह और देर शाम ठंड का असर बना रहता है, जबकि दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है। तापमान के इस उतार-चढ़ाव ने सर्दी-जुखाम, वायरल बुखार और गले के संक्रमण जैसी मौसमी बीमारियों को तेजी से बढ़ावा दिया है।

जिला चिकित्सालय की ओपीडी में मरीजों की संख्या में अचानक उछाल दर्ज किया गया है। पिछले आठ दिनों में करीब 6 हजार मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जिनमें लगभग 648 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पर्ची काउंटर पर भीड़ का दबाव इतना अधिक है कि कई मरीजों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

ओपीडी में आने वाले अधिकांश मरीज खांसी, बुखार, गले में खराश, सिरदर्द और बदन दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौसम परिवर्तन के दौरान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है। विशेष रूप से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने, ठंडी वस्तुओं से परहेज करने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके।

मौसमी बीमारियों का असर छोटे बच्चों में अधिक देखा जा रहा है। शिशु रोग विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन 100 से अधिक बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से 8 से 10 बच्चों को गंभीर लक्षणों के चलते भर्ती करना पड़ रहा है। सर्दी-खांसी के साथ निमोनिया के शुरुआती संकेत भी सामने आ रहे हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ी है।

चिकित्सकों का कहना है कि समय पर उपचार मिलने पर 4 से 5 दिनों में स्थिति नियंत्रित हो सकती है, लेकिन लापरवाही बरतने पर संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 30 से 40 बच्चे सर्दी-खांसी और जुकाम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, वहीं जिला चिकित्सालय में रोजाना 90 से 100 बच्चों की ओपीडी दर्ज की जा रही है। 19 से 26 फरवरी के बीच भी स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव बना रहा। इस अवधि में ओपीडी में कुल 6 हजार मरीज पहुंचे, जबकि 650 बच्चों को आईपीडी में भर्ती किया गया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने पंजीयन और उपचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

प्रेस वार्ता

किसान, युवा, बेरोजगार एवं महिलाओं की तरक्की को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है बजट

प्रदेश के बजट से होगा सर्व समाज का सर्वांगीण विकास

विजय मत, शहडोल

मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अटल निलय जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में तथा उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत यह बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला दूरदर्शी दस्तावेज है। जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा ने बजट का स्वागत करते हुए इसे सर्वसमाज के समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण, किसान हित और युवा उन्नति पर केंद्रित बताया।

पत्रकार वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा जी एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष बजट 2026 के संयोजक मनोज गुप्ता, सहसंयोजक राजकुमार खरया, जिला कोषाध्यक्ष अमित गुप्ता बंटी, जिला मीडिया प्रभारी विनय केवट पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहे पत्रकार वार्ता का मंच संचालन भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विनय केवट ने किया एवं आभार जिला उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने किया।

विकास को गति देने वाला रोलिंग बजट-

श्रीमती अमिता चपरा ने बताया कि इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग साढ़े चार प्रतिशत अधिक प्रावधान के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह प्रदेश का पहला ÷रोलिंग बजट÷ है, जो आगामी तीन वर्षों के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है। बजट को डिजिटल, पारदर्शी और जनता-केंद्रित बताया गया है। विशेष बात यह है कि लगातार तीसरी बार कोई नया कर नहीं बढ़ाया गया है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता-

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को ÷किसान कल्याण वर्ष÷ घोषित किया गया है। किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक लाख सोलर पंप वितरण की योजना से किसानों को बिना अतिरिक्त बिजली लागत के सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

किसान कल्याण योजना हेतु 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें फसल बीमा, ब्याज-मुक्त ऋण एवं अन्य सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान रखा गया है।

युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण-

श्रीमती चपरा ने कहा कि बजट युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने वाला है। महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए समर्पित योजनाओं में 'लाड़ली बहना' जैसी योजनाओं को मजबूती दी गई है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण एवं कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक निवेश प्रस्तावित है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े प्रावधान-बजट में 200 नए संदीपनी स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। मेडिकल कॉलेजों में कैंसर एवं हृदय रोगों के सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित किए जाएंगे, जिससे गंभीर रोगों के उपचार के लिए प्रदेशवासियों को बाहर न जाना पड़े। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण तथा महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है।

प्रधानमंत्री के विजन का प्रतिबिंब -अपने संबोधन में श्रीमती चपरा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों का प्रतिबिंब है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सर्वसमाज के लिए सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

किसान, फसल हानि वाले रोगों एवं कीटों से बचाव हेतु सौर ऊर्जा का करें उपयोग

शहडोल। जैविक खेती अंतर्गत मृदा सूर्यीकरण पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय इंदिरा गांधी होम साइंस कॉलेज शहडोल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. ब्रजकिशोर प्रजापति ने प्रशिक्षार्थियों को बताया कि कई दशकों से फसलों के उत्पादन वृद्धि हेतु रसायनों जैसे उर्वरकों, कीटनाशक एवं खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग बढ रहा है जो कि मानव समाज व पर्यावरण दोनों के लिए अत्यन्त हानिकारक है। इसी वजह से वर्तमान में प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। किसान की बोई गई फसलों की नर्सरी को भूमि जनित कीटं, रोग और खरपतवार से भारी नुकसान होता है। यह भूमि जनित कीटं, रोग और खरपतवार खेत की मिट्टी में पहले से ही पड़े रहते है और अनुकूल मौसम मिलते ही खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाते है। अधिकतर किसान जमीन मे छिपे इन रोगों, कीटों से निपटने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण और जीव-जंतु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान साथियों को फसलों के उत्पादन को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों, कीटों व खरपतवारों से बचाव के लिए सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग करना चाहिए। अगर किसान खेती की जाने वाली जगह का मृदा सौरीकरण कर लें तो इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मृदा सूर्यीकरण तकनीक में पारदर्शी पालीथीन (प्लास्टिक मल्चिंग) से वर्ष के अधिक तापमान वाले महीनों (मई-जून) में सिचाई उपरान्त खाली पड़े खेत को ढक देते हैं और पालीथीन के किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह दबा देते हैं, ताकि मृदा में अवशोषित एवं संचयित ताप बाहर न निकल सकें। जिसके फलस्वरूप खेत की सतह पर तापमान में लगभग 8-12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है।

न्यूज इन शॉर्ट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के इज़रायली संसद में सम्मान पर किया अभिनंदन

विजय मत, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इज़रायली संसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ द नेसेट' मेडल से सम्मानित करने पर उनका अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि यह संपूर्ण भारत के लिए बेहद गौरवशाली क्षण हैं। इजरायली संसद से मिला यह सम्मान नए भारत की वैश्विक पहचान, विश्वास और बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी, इजरायल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। करीब 9 साल बाद उनकी इजरायल की यह दूसरी यात्रा है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भेंट कर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

मंत्री अब चेक से बांटेंगे स्वेच्छानुदान

विजय मत, भोपाल। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के स्वेच्छानुदान को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब मंत्री के स्वेच्छानुदान मद से किसी भी हितग्राही या संस्था को राशि का आवंटन ई-भुगतान प्रणाली से नहीं होगा। इसकी जगह अब चेक जारी होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मंत्रियों का स्वेच्छानुदान मद 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, राज्यमंत्री का मद 60 होता है। जबकि मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान मद 200 करोड़ होता है। विभाग के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान से 284 आदेशों में 1 करोड़ 61 लाख से ज्यादा का ई-भुगतान हो चुका है।

आरजीपीसी में रैंगिक का मामला

विजय मत, भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सीनियर ने जुनियर छात्रो द्वारा की गई मारपीट के बाद रैंगिंग लेने की शिकायत दर्ज कराई है। घटना की शिकायत यूजीसी की एंटी रैंगिंग हेल्पलाइन पर दर्ज की गई है। हेल्पलाइन ने प्रकरण को आरजीपीवी को फारवर्ड किया है। इसके बाद आरजीपीवी घटनाक्रम में जुड़े विद्यार्थियों की तलाश कर कार्रवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक तीन जूनियर विद्यार्थी का एक सीनियर विद्यार्थी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तब सीनियर ने जूनियर छात्रो से दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट करनी शुरु कर दी। इस पर प्रथम वर्ष के एक और द्वितिय वर्ष के दो विद्यार्थियों ने मिलकर चौथे वर्ष के सीनियर विद्यार्थी की जमकर पिटाई कर दी। जूनियर विद्यार्थियों से पिटने के बाद सीनियर ने एंटी रैंगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक हेल्पलाइन से ई-मेल मिलने के बाद आरपीजीवी द्वारा घटना की जॉच करते हुए प्रकरण से संबंधित विद्यार्थियों को नोटिस देकर तलब किया जाएगा। जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जायेगी।

चाकूबाजी के आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास

विजय मत, भोपाल। राजधानी की जिला अदालत ने चाकूबाजी के आरोपी को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति साल्वे की कोर्ट ने आरोपी तरुण उर्फ अच्छू सिंह सोलंकी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास सहित 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर 2022 की रात करीब साढ़े दस बजे आरोपी अच्छू उर्फ अक्षय सिंह ने शराब के लिए मोनू पर पॉच सौ रुपये की अड़ीबाजी की और रकम नहीं देने पर उससे विवाद करते हुए घर की बालकनी में पहुंचकर गाली-गलौज करने लगा। बीच-बचाव करने पर उसने फरियादी की कलाई पर चाकू से वार किया वहीं बचाने आए उसके पिता पर भी वार कर उंगली में भी चोट पहुंचाई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था।

चोरो ने ताले से चाबी खोली और लॉकर उठा कर ले गये

विजय मत, भोपाल। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अजीबो गरीब चोरी की घटना सामने आई है। यहॉ चोरों ने चाबी से मकान का ताला खोला और इसके बाद भारी भरकम लॉकर उठा कर चंपत हो गए। चोरी गये लॉकर में लाखों रुपए के जेवरात रखे थे। जॉच के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना पुलिस के अनुसार राधा यादव पti स्वर्गीय राजेश यादव (40) ने लिखित शिकायत करते हुए बताया की वह लखेरापुरा में कटपीस वाली गली में किराए से रहती हैं, और सिलाई का काम करती है।

प्रदेश में सीवेज प्रबंधन की गंभीर स्थिति उजागर

रोज निकलने वाले सीवेज में से सिर्फ 33% का हो रहा उपचार, नर्मदा-शिप्रा में मिल रहा गंदा पानी

विजय मत, भोपाल

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों से प्रतिदिन 2,183 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज निकल रहा है, लेकिन इसमें से केवल लगभग 1,500 एमएलडी यानी करीब 33 प्रतिशत का ही उपचार हो पा रहा है। शेष सीवेज बिना शोधन के सीधे नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित हो रहा है। यह तथ्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा तैयार हालिया रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट ने प्रदेश की जल प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति नर्मदा और शिप्रा जैसी प्रमुख नदियों की बताई गई है। इन नदियों के किनारे बसे नगरीय निकायों से निकलने वाला सीवेज कई स्थानों पर बिना उपचारित ही जलधाराओं में मिल रहा है। इससे नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और जलीय जीवन के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हाल ही में दूषित पेयजल की घटना सामने आने के बाद यह मुद्दा और गंभीर हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार सीवेज के पानी में ई-कोलाई सहित अनेक हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो जलजनित रोगों जैसे डायरिया, टाइफाइड और हैजा का कारण बन सकते हैं। यदि यह पानी पेयजल स्रोतों में मिल जाता है तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की स्थिति

राज्य सरकार का कहना है कि स्थिति सुधारने के लिए प्रयास जारी हैं। वर्तमान में प्रदेश में 223 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माणाधीन हैं, जबकि 225 नए एसटीपी प्रस्तावित हैं। इनके पूर्ण होने के बाद सीवेज उपचार की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। सीवेज ट्रीटमेंट एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें गंदे पानी से ठोस अपशिष्ट, कार्बनिक पदार्थ और रोगजनक जीवाणुओं को हटाया जाता है।

नर्मदा पर एनजीटी की सख्ती

नर्मदा नदी में सीवेज मिलने के मामलों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंभीरता से लिया है। अधिकरण ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना उपचारित सीवेज और रसायनयुक्त जल को नदी में प्रवाहित होने से रोका जाए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल को नियमित निगरानी और सैंपलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडल द्वारा समय-समय पर लिए गए जल नमूनों की जांच से कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर मानकों से अधिक पाया गया है।

औद्योगिक प्रदूषण पर दावा

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 32,823 उद्योग संचालित हैं, जिनमें से 2,324 उद्योग जल प्रदूषणकारी श्रेणी में आते हैं। इन उद्योगों से प्रतिदिन 640 एमएलडी दूषित जल उत्पन्न होता है, जबकि उपचार क्षमता 913 एमएलडी बताई गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का दावा है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपचार के बाद ही जल छोड़ा जा रहा है। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि औचक निरीक्षण और कड़ी निगरानी आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र सबसे बड़ी चुनौती

नगरीय क्षेत्रों में अमृत-2 जैसी योजनाओं के माध्यम से सीवेज प्रबंधन पर कार्य हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाला लगभग 6,500 एमएलडी सीवेज है। अधिकांश गांवों में सीवेज उपचार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। घरेलू अपशिष्ट जल सीधे नालों और तालाबों में बहा दिया जाता है, जिससे भूजल और सतही जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में भी छोटे पैमाने के एसटीपी या विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इससे जल संरक्षण और पुनर्भरण की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बिना उपचारित सीवेज का प्रवाह जारी रहा तो प्रदेश में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा नदी-तालाबों की जैव विविधता प्रभावित होगी और पेयजल परियोजनाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। जल संसाधनों की रक्षा के लिए सीवेज प्रबंधन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अधूरी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना, निगरानी तंत्र को मजबूत करना और जनजागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

बाघों की कम आबादी वाले राज्यों में मप्र के बाघ बढ़ाएंगे कुनबा

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा भेजे जाएंगे 8 टाइगर

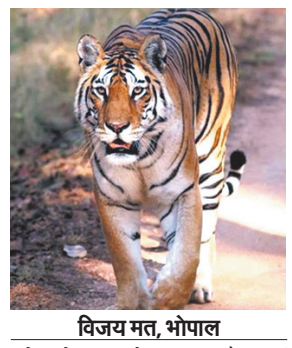

विजय मत, भोपाल

प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ कई ऐसे राज्य हैं, जहां बाघों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। पर्यावरण और वन्यप्राणियों का महत्व समझते हुए अब ये राज्य बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों की जहां बाघों की संख्या एक सैकड़ा पार भी नहीं हो पायी है। यहां बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाघ मांगे गए हैं। हालांकि, राजस्थान को एक बाघ हाल ही में दिसंबर में भेज दिया गया है। लेकिन अन्य राज्यों को बाघ भेजे जाने के लिए अभी उनकी मांग का इंतजार किया जा रहा है। इन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश से कुल 8 बाघ भेजे जाएंगे।

बाघ शिफ्टिंग की तमाम औपचारिकताएं पूरी

इन राज्यों की मांग पर एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघ शिफ्टिंग के लिए होने वाली तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ शुभरंजन सेन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघों की शिफ्टिंग के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से औपचारिकताएं पूरी होती है। मांग करने वाले राज्यों को एनटीसीए से अपील करनी होती है। फिर एनटीसीए जिस राज्य में बाघों की संख्या ज्यादा होती है, उनसे बाघों की शिफ्टिंग के लिए सहमति मांगता है और सहमति के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा बाघ मांगने वाले राज्यों में रिसर्च करायी जाती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के आधार पर एनटीसीए बाघों की शिफ्टिंग की अनुमति देता है।

तीनों राज्यों में बाघों की संख्या 100 से कम

जहां तक मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड की बात करें, तो ये देश के तीन ऐसे राज्य हैं जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां बाघों की संख्या शून्य है और कुछ राज्य ऐसे भी है जहां बाघों की संख्या 100 से ऊपर तक नहीं हो पायी है।

अतिथि शिक्षकों के विरोध का असर

शिक्षा विभाग ने एक हफ्ते गैरहाजिर तो रिलीव वाला लिया आदेश वापस

विजय मत, भोपाल

अतिथि शिक्षकों को एक हफ्ते गैरहाजिर रहने पर उन्हें सेवा से तुरंत रिलीव करने का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने वापस ले लिया है। अतिथि शिक्षकों के बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्ति संबंधी इस आदेश का प्रदेशभर में विरोध हुआ। अतिथि शिक्षकों ने इसे कठोर बताते हुए आपत्ति जताई, जिसके बाद विभाग को कदम पीछे खींचना पड़ा। दरअसल 20 फरवरी को जारी निर्देशों में कहा गया था कि जो अतिथि शिक्षक लगातार एक सप्ताह तक स्कूल नहीं आते, उन्हें पोर्टल पर दर्ज अटेंडेंस के आधार पर तत्काल रिलीव किया जाए।

यह थे सख्त निर्देश

- लगातार 7 दिन अनुपस्थित रहने पर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त (रिलीव) करने का आदेश।
- स्कूल प्रभारी और प्राचार्यों पर कार्रवाई की चेतावनी, यदि वे लंबी अनुपस्थिति के बावजूद कदम नहीं उठाते।
- पोर्टल आधारित अटेंडेंस के आधार पर एक सप्ताह से अधिक गैरहाजिर शिक्षकों को तुरंत हटाने के निर्देश।
- कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात।

अब आदेश को निरस्त किया

26 फरवरी को जारी नए पत्र में पहले वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद इस संबंध में अलग से नए निर्देश जारी किए जाएंगे। इस फैसले के बाद अतिथि शिक्षकों को फिलहाल राहत मिली है, जबकि आगे की कार्रवाई पोर्टल अपडेट के बाद तय होगी।

एक प्रदेश में दो तरह का आरक्षण अन्याय

रजक समाज के प्रदर्शन में उठी क्षेत्रीय बंधन हटाने की मांग

विजय मत, भोपाल

संयुक्त मोर्चा रजक समाज के नेतृत्व में गुरुवार को राजधानी में आयोजित आंदोलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। सभा स्थल पर धरना-प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने साफ कहा कि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं आकर समाज की बात नहीं सुनेंगे, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने एहतियातन बैरिकेडिंग कर दी है। दोपहर बाद सीएम हाउस कूच की भी चेतावनी दी गई है। संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ संयोजक कैलाश नाहर ने कहा कि मध्यप्रदेश में रजक समाज को केवल तीन जिलों भोपाल, सीहोर और रायसेन में अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, जबकि बाकी 52 जिलों में यही समाज ओबीसी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम लगातार राज्य शासन से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह तीन जिलों में एससी का दर्जा है, उसी तरह पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। एक ही समाज के साथ अलग-अलग जिलों में अलग आरक्षण व्यवस्था सामाजिक अन्याय है। नाहर ने बताया कि समाज ने अपनी मांग को लेकर 400 से 500 किलोमीटर तक की पैदल यात्राएं कीं।

क्षेत्रीय बंधन हटे, 70-75 साल का संघर्ष

युवा प्रदेश संयोजक मोनू लक्ष्मण रजक ने कहा कि समाज की मुख्य मांग क्षेत्रीय बंधन हटाने की है। उन्होंने कहा, कहने को देश आजाद है, लेकिन रजक समाज आज भी बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। हमारी श्रेणी अनुसूचित जाति में आती है, लेकिन सरकार ने क्षेत्रीय बंधन लगा रखा है। इसी बंधन को हटाना हमारी सबसे बड़ी मांग है। मोनू ने कहा कि यह संघर्ष आज का नहीं है, बल्कि करीब 70-75 वर्षों से समाज के वरिष्ठजन लड़ते आ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया, लेकिन समाज को समय नहीं दिया गया।

बढ़ने लगी तपिश, इन जिलों में 30 के पार हुआ पारा, मार्च में फिर बारिश का अलर्ट

विजय मत, भोपाल

मध्य प्रदेश में लगातार आंधी, बारिश और ओलों की मार झेलने के बाद अब मौसम ने बदलाव आ गया है। सुबह से धूप के तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। विगत दिनों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत 28 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया। जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, निमाड़ अंचल के खरगोन और खंडवा में तापमान 34 डिग्री के पार जाने से ये क्षेत्र प्रदेश में सबसे गर्म रहा। उज्जैन में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

बढ़ रहा तापमान

दिन के साथ रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कुछ जगहों पर ठंड महसूस की जा रही है। जिसमें भोपाल में 13.8, इंदौर में 14.2, ग्वालियर में 14.8, उज्जैन में 16.5 और जबलपुर में 14.5 डिग्री दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में रात का तापमान 18.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा।

मार्च में फिर बदलेगा मौसम!

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालय के इलाकों में नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। जिसके चलते मार्च के शुरूआत से मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। इसी के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।

ग्वालियर-भिंड-इटावा एनएच-719 बनेगा फोर लेन

एनएचएआई की डीपीआर अंतिम चरण में; 117 किमी का सफर होगा आसान

विजय मत, भोपाल

मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोडने वाला महत्वपूर्ण एनएच-719 (ग्वालियर-भिण्ड-इटावा) अब जल्द ही फोर लेन हाईवे में तब्दील होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जिम्मेदारी मिलने के बाद एनएचएआई अब अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 117 किलोमीटर रहेगी। मौजूदा हालत में इस 2 लेन रोड पर अत्यधिक यातायात दबाव रहता है। इसके चलते इसे फोर लेन बनाया जाएगा। इसमें बायपास निर्माण और ब्लैक स्पॉट्स का खात्मा हो जाएगा। वर्तमान में हर दिन तकरीबन 20 हजार वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं।

फोर लेन बनने के 5 बड़े फायदे: फोर लेन बनने के बाद शहरों में प्रस्तावित बायपास के कारण भारी वाहनों को शहर के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। मार्ग पर मौजूद ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) को समाप्त किया जाएगा। क्रैश बैरियर और आधुनिक रोड मार्किंग से यात्रा सुरक्षित होगी।

फोर लेन होने से वाहनों की गति बढ़ेगी, जिससे ग्वालियर से इटावा के बीच यात्रा समय में भारी गिरावट आएगी। बेहतर कनेक्टिविटी से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, कृषि परिवहन और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। एमपी और यूपी के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और परिवहन लागत में कमी आएगी। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार, यह परियोजना ग्वालियर-चंबल संभाग के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया जा चुका है ताकि परियोजना के क्रियान्वयन में कोई देरी न हो।

रेल यात्रियों के हित में दो बड़े सुधार: नवाचार को बढ़ावा और दावा मामलों में डिजिटल क्रांति

विजय मत, भोपाल

भारतीय रेल ने यात्रियों और आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और आधुनिक सेवाएं देने की दिशा में दो महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। इनमें पहला सुधार रेल टेक नीति के रूप में नवाचार और तकनीकी समाधान को बढ़ावा देने से जुड़ा है, जबकि दूसरा सुधार ई-आरसीटी के जरिए रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मामलों की प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर सरल करने से संबंधित है। इस नीति के तहत प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया को एक ही चरण में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाया गया है। साथ ही, समाधान को बड़े स्तर पर लागू करने हेतु मिलने वाला स्केल-अप ग्रांट' तीन गुना से अधिक बढ़ाया गया है तथा प्रोटोटाइप विकास और परीक्षण के लिए अधिकतम अनुदान भी दोगुना किया गया है। पोर्टल को उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस के साथ तैयार किया गया है। नीति के अंतर्गत जिन प्रकार की नवाचार चुनौतियां दर्शाई गई हैं, उनमें एआई आधारित हाथी घुसपैठ पहचान प्रणाली, कोचों में एआई आधारित अग्नि पहचान प्रणाली, ड्रोन आधारित टूटी रेल पहचान, रेल तनाव निगरानी प्रणाली, पार्सल वैन में सेंसर आधारित भार गणना उपकरण, कोचों पर सौर पैनल, एआई आधारित कोच सफाई निगरानी तथा धुंध में बाधा पहचान जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है।

रेल टेक नीति: इस नई नीति का उद्देश्य नवोन्मेषकों, स्टार्टअप, उद्योग एवं संस्थानों को भारतीय रेल के साथ जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत नवोन्मेषकों के चयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और नवाचार के लिए नया रेल टेक पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा।

भोपाल के वल्लभ भवन-सतपुड़ा एवं विंध्याचल में हाजिरी पर सख्ती

सीएम के निर्देश पर शुरू हुई मॉनिटरिंग, जीएडी के अधिकारियों ने चेक किए उपस्थिति रजिस्टर

विजय मत, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद राजधानी के तीन प्रमुख शासकीय कार्यालय (वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन) में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधिकारियों ने आज सुबह 10 बजे सभी प्रमुख विभागों के कार्यालय में जाकर उपस्थिति रजिस्टर चेक किए। वहीं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी ऐसा करने को कहा। इन कार्यालयों में कौन अधिकारी-कर्मचारी कब पहुंचा और कब वापस गया, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों की आवाजाही पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि उपस्थिति संबंधी जानकारी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संकलित की जाएगी। बताया गया है कि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन वर्तमान में भोपाल से बाहर दौरे पर हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग को सभी संबंधित दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति, आने-जाने का समय और अनाधिकृत अनुपस्थिति की जानकारी एकत्र करने के आदेश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की टीमें तीनों भवनों में तैनात होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

समय पालन पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जनकल्याणकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी अधिकारी और कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संदेश दिया है कि यदि समय पालन में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि जनता की सुविधा और पारदर्शी प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पूर्ण जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

विजय मत एंकर 10 मार्च तक जमा करना अनिवार्य; नई दरें 2026-27 सत्र से लागू, देरी पर समाप्त होगी

डीएलएड संस्थाओं की संबद्धता फीस बढ़ी

विजय मत, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2026-27 से डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के लिए संबद्धता, नवीनीकरण और अतिरिक्त इंटेक की फीस बढ़ा दी है। कार्यपालिका समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद संशोधित आदेश जारी कर नई दरें लागू कर दी गई हैं। संस्थाओं को 10 मार्च 2026 तक निर्धारित शुल्क यूको बैंक की निर्दिष्ट शाखा या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा कर आवेदन की प्रति मंडल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। तय समय सीमा तक राशि जमा नहीं होने पर संबंधित संस्था की संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मंडल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डीएलएड की परीक्षाओं के लिए पहली बार संबद्धता शुल्क 1 लाख 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी एकमुश्त 50 हजार रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के अतिरिक्त इंटेक के लिए भी शुल्क 1 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यह भी एक बार देय होगा।

वार्षिक शुल्क में बढ़ोतरी

50 विद्यार्थियों के इंटेक पर शुल्क 22,500 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया है। 100 विद्यार्थियों के इंटेक पर 45,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए। 150 विद्यार्थियों के इंटेक पर 75,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए निर्धारित किया गया है। संस्थाओं को शुल्क माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल परिसर स्थित यूको बैंक, हबीबगंज शाखा में सचिव के नाम चालान के माध्यम से जमा करना होगा। किसी अन्य बैंक का चालान मान्य नहीं होगा। इसके अलावा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित खाता क्रमांक और आईएफएससी कोड जारी किया गया है।

10 मार्च अंतिम तिथि

सत्र 2026-27 के लिए नई संबद्धता, नवीनीकरण या अतिरिक्त इंटेक के आवेदन 10 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से मंडल कार्यालय में जमा करने होंगे। आवेदन के साथ शुल्क जमा करने का प्रमाण भी संलग्न करना जरूरी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय तिथि तक राशि जमा नहीं होने पर पूर्व आदेश के प्रावधानों के तहत संबंधित संस्था की संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। मंडल ने सभी संस्थाओं से समय सीमा का पालन करने और नियमों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए।

संस्थापक
श्री रामसिपाही शुक्ल

विधायकों के टेलीफोन भत्ते फिजूलखर्ची या जनसंपर्क की अनिवार्यता है?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं हमेशा चर्चा और बहस का विषय रही हैं। वेतन और भत्तों का मूल उद्देश्य यह माना जाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि आर्थिक चिंता से मुक्त होकर जनता की सेवा कर सकें। लेकिन जब इन सुविधाओं का आकार बढ़ता है और उनके उपयोग में पारदर्शिता कम दिखाई देती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा विधायकों और विधान पार्षदों के लिए मासिक टेलीफोन भत्ता बढ़ाकर 8300 रुपये करने का निर्णय सामने आया है। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि यह राशि बिना किसी बिल या वाउचर के दी जाएगी। यानी खर्च का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं होगा। यही कारण है कि यह विषय अचानक सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गया है।आज का भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने संचार के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। कुछ साल पहले तक कॉल दरें और डेटा पैक महंगे हुआ करते थे, लेकिन अब निजी टेलीकॉम कंपनियों के कारण संचार सेवाएं काफी सस्ती हो चुकी हैं। आम नागरिक 300 से 400 रुपये के मासिक रिचार्ज में अनलिमिटेड कॉल, डेटा और संदेश की सुविधा प्राप्त कर लेता है। ऐसे समय में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब देश का आम व्यक्ति इतनी कम राशि में अपना संचार चला सकता है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए हजारों रुपये का अलग भत्ता क्यों आवश्यक है।

बिहार के इस निर्णय ने एक व्यापक बहस को जन्म दिया है। राज्य में कुल 243 विधायक हैं। यदि हर विधायक को प्रति माह 8300 रुपये का टेलीफोन भत्ता दिया जाता है, तो सालाना यह राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है। आलोचकों का कहना है कि यह पैसा सार्वजनिक धन है और इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास या अन्य जरूरी क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे अनावश्यक खर्च या राजनीतिक विशेषाधिकार के रूप में देख रहे हैं।हालांकि इस विषय का दूसरा पक्ष भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनप्रतिनिधियों का काम केवल विधानसभा तक सीमित नहीं होता।

सूचना

सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख-आलेख एवं विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। अतः यह जरूरी नहीं है कि विजय मत समूह उपरोक्त लेख या विचारों से सहमत हो। किसी लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार हैं।

एक बार साफ-साफ बतला दो आप करोगे कि नहीं .....

चैतन्य भट्ट

प्रदेश में निगमों, मंडलों आयोगों प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा है अपने को तो ये मालूम था कि हर चीज का अंत हो जाता है लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपने ही प्रदेश में निगमों, मंडलों आयोगों, प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का अंत कभी नहीं होगा । कितने सावन, कितने फागुन, कितने माघ, कितने पूस, कितने जेठ, कितने बैसाख, और भी न जाने कितने मौसम निकल गए, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, ठंड निकल गई अब फिर गर्मी आने वाली है लेकिन नियुक्तियों का नियुक्ति पत्र अभी तक किसी भी नेता के पास नहीं पहुंचा । पहले बिहार चुनाव की फांस, फिर मुख्यमंत्री का लफड़ा, फिर महाराष्ट्र निकाय निकायों के चुनाव, फिर महापौरों की झंझट, फिर पुराना साल, फिर नया साल, फिर मकर संक्रांति, फिर गणतंत्र दिवस, फिर बड़ा दिन, फिर बताया गया कि नहीं अब फरवरी के फर्स्ट वीक में तो किसी भी परिस्थिति में ये तमाम नियुक्तियां कर ही दी जाएंगी, वे तमाम नेता जो बेचारे पिछले तीन साल से इंतजार कर रहे थे खुश हो गए कि अब तो सारे कंटक दूर हो चुके हैं नियुक्तियां हो ही जाएंगी,लेकिन फिर एक खबर आई कि नहीं नहीं अभी इसकी आशा मत करो क्योंकि अभी प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है अब जब बजट आ गया है तो उसका क्या रिपरकेशन जनता पर पड़ता है उसके बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा। 18 तारीख को प्रदेश का बजट भी आ गया नेताओं ने बजट के तारीफों के पुल भी बांध दिए बता दिया कि आज तक ऐसा बजट आया ही नहीं। अब तो नियुक्ति दे दो भैया लेकिन -चार दिन तो बीत गए अभी तक नियुक्तियों की कोई खबर है नहीं । जो नेता मंडलों निगमों, प्राधिकरणों आयोगों में नियुक्ति की राह देख रहे हैं उनके कुर्ते पजामे का कलफ टूट गया, सफेद कुर्ते पैजामे मैले हो गए लेकिन कोई खबर नहीं आई। अपने को तो समझ में नहीं आता कि यदि हाई कमान को इन में नियुक्ति नहीं करना है तो एक बार साफ-साफ उन उम्मीदवारों को बता क्यों नहीं दिया जाता कि तुम लोग बेवजह परेशान मत हो और ना ही आशा करो, हम लोग कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे एक बार साफ-साफ बता दोगे तो कम से कम रोज-रोज की झंझट और रोज के इंतजार से तो उन तमाम नेताओं को मुक्ति मिल जाएगी जो पिछले तीन साल से अपनी आंखों में आशा का दीप जलाए बैठे हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने वाले राष्ट्र ऋषि नानाजी

सुरेन्द्र शर्मा

सक्रिय राजनीति में ऊँचे पदों तक पहुँचने के बावजूद नानाजी देशमुख ने 60 वर्ष की आयु में राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण समाज का पुनर्निर्माण है। उन्होंने स्वयं को ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया।नानाजी देशमुख ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। उनके अनुसार विकास का केंद्र गांव होना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट क्षेत्र को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। नानाजी देशमुख और भारतीय जनसंघ नानाजी देशमुख का नाम भारतीय जनसंघ के प्रमुख संगठनकर्ताओं और रणनीतिकारों में से एक है।

नानाजी देशमुख के यह वाक्य केवल उनके ही जीवन का ध्येय वाक्य नहीं था बल्कि उनके पदचिन्हों पर चलकर हजारों लोगों ने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसका परिणाम आज चित्रकूट गोंडा और अन्य जिलों में देखा जा सकता है।नानाजी देशमुख का नाम भारतीय सार्वजनिक जीवन में एक ऐसे कर्मयोगी के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने राजनीति को समाजसेवा का माध्यम बनाया और बाद में सक्रिय राजनीति छोड़कर पूर्णकालिक ग्रामोदय के कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, राष्ट्रभक्ति, संगठन कौशल और ग्राम विकास की प्रयोगधर्मिता का अद्भुत संगम था। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक और चिंतक थे।नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के परभणी जिले के कडोली गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम चंडिकादास अमृतराव देशमुख था। बाल्यकाल से ही वे परिश्रमी, आत्मनिर्भर और राष्ट्रभावना से ओत-प्रोत थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश में संघ के विस्तार में विशेष योगदान दिया।नानाजी देशमुख भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया। वे उत्तर प्रदेश में जनसंघ के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते थे। उनकी कुशल रणनीति के कारण 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिली और कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं।1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब नानाजी देशमुख लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रहे। उन्होंने भूमिगत रहकर विरोध आंदोलन को संगठित किया। आपातकाल के विरुद्ध जनांदोलन में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। बाद में वे जनता पार्टी के गठन में भी सक्रिय रहे और 1977 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए।

सक्रिय राजनीति में ऊँचे पदों तक पहुँचने के बावजूद नानाजी देशमुख ने 60 वर्ष की आयु में राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण समाज का पुनर्निर्माण है। उन्होंने स्वयं को ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया।नानाजी देशमुख ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। उनके अनुसार विकास का केंद्र गांव होना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट क्षेत्र को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। नानाजी देशमुख और भारतीय जनसंघ

नानाजी देशमुख का नाम भारतीय जनसंघ के प्रमुख संगठनकर्ताओं और रणनीतिकारों में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे उन नेताओं में थे जिन्होंने जनसंघ को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और उसे एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। नानाजी देशमुख प्रारंभ से ही इस दल से जुड़े और संगठन विस्तार का दायित्व संभाला। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे थे, इसलिए संगठन निर्माण और कार्यकर्ता तैयार करने में उनकी विशेष दक्षता थी।उत्तर प्रदेश में जनसंघ को मजबूत बनाने का श्रेय मुख्यतः नानाजी देशमुख को जाता है। उन्होंने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया। उनकी रणनीति थी कि पहले मजबूत संगठन बनाया जाए, फिर चुनावी सफलता स्वतः मिलेगी।नानाजी देशमुख का राजनीतिक दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था। वे मानते थे कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि वैचारिक संघर्ष और राष्ट्र निर्माण का साधन है।1967 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने में उनकी रणनीति महत्वपूर्ण रही। उस समय गैर-कांग्रेसी दलों को एकजुट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामस्वरूप कई राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनीं।वे पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने में विश्वास रखते थे। व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहकर उन्होंने पार्टी के लिए कार्यकर्ता-आधारित संरचना विकसित की।

नानाजी देशमुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन से अत्यंत प्रभावित थे। जनसंघ की नीतियों में इस विचारधारा को स्थापित करने में उनका योगदान रहा वे मानते थे कि भारतीय राजनीति को पश्चिमी विचारधाराओं की नकल करने के बजाय भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जनसंघ के कार्यक्रमों और नीतियों में राष्ट्रीयता, स्वदेशी और सामाजिक समरसता पर जोर देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, तब जनसंघ के अनेक नेता गिरफ्तार किए गए। नानाजी देशमुख ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। वे भूमिगत रहकर आंदोलन को संगठित करते रहे।

आपातकाल के विरोध में जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के प्रयासों में भी उनका योगदान रहा। 1977 में जनता पार्टी के गठन में जनसंघ का विलय हुआ और उस ऐतिहासिक परिवर्तन में नानाजी देशमुख की रणनीतिक भूमिका मानी जाती है।जनसंघ और बाद में जनता पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान रखने के बावजूद नानाजी देशमुख ने 60 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति छोड़ दी। उनका मानना था कि नए नेतृत्व को आगे आना चाहिए और वे स्वयं समाजसेवा के कार्यों में लग गए। यह निर्णय उनकी त्यागमयी प्रवृत्ति और आदर्शवादी सोच का प्रमाण था। उन्होंने सिद्ध किया कि उनके लिए पद या सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र और समाज की सेवा है।नानाजी देशमुख और भारतीय जनसंघ का संबंध केवल एक नेता और दल का नहीं था, बल्कि वह एक वैचारिक और संगठनात्मक साझेदारी थी। उन्होंने जनसंघ को जमीनी स्तर पर मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और वैकल्पिक राजनीति की नींव को सुदृढ़ बनाया। उनका योगदान भारतीय राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंघ की संगठनात्मक शक्ति और वैचारिक स्पष्टता के पीछे नानाजी देशमुख जैसे समर्पित नेताओं का अथक परिश्रम था।

नानाजी देशमुख भारतीय सार्वजनिक जीवन के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने ग्राम विकास को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बना लिया। उनका विश्वास था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांव आत्मनिर्भर, शिक्षित और समृद्ध नहीं होंगे, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)- साभार

स्मार्टफोन ने याददाश्त छीनी एआई कल्पना शक्ति छीन लेगी?

रमेश गौर

एआई तकनीकी से इलाज होगा। इसे एआई क्रांति का नाम दिया जा रहा है। यह क्रांति आएगी, उसके बाद आदमी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसे एक बड़ी औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। धरती में सभी को सब कुछ बैठे-बैठे मिल जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। एआई तकनीकी के दुष्प्रभाव को लेकर युवल नोआ हरारी ने अपनी किताब नेक्सस में एआई के खतरों से आगाह किया है। उन्होंने दावा किया है, पहली बार मनुष्य सभ्यता के सामने एक ऐसी मशीनी दुनिया खड़ी होने जा रही है जो मनुष्य से अधिक बुद्धिशील और पराक्रमी साबित होगी। इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक भी हो सकता है। एआई तकनीकी आने के बाद जिस तेजी के साथ मशीनें अपने आप को अपग्रेड कर लेती हैं।

भारत से लेकर दुनिया के सभी देशों में इस समय एआई की धूम मची हुई है। हर वर्ग का व्यक्ति छोटा हो या बड़ा इसी तकनीकी की बात कर रहा है। सबको ऐसा लग रहा है, यदि यह तकनीकी हमारे पास नहीं आई तो शायद हम अपना सब कुछ खो देंगे। भारत में हाल ही में एआई समिट हुआ है। जिसमें दुनिया भर के देशों से एआई की आईटी कंपनियों ने बड़े-बड़े दावे किए हैं। ऐसा लग रहा है, जल्द ही स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। एआई तकनीकी आने के बाद जो खतरे आने वाले हैं, उसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। दिल्ली में हुए समिट के दौरान कहा गया, इस तकनीकी से कारोबार आसान हो जाएगा। खेती बहुत बढ़िया हो जाएगी। एआई तकनीकी से इलाज होगा। इसे एआई क्रांति का नाम दिया जा रहा है। यह क्रांति आएगी, उसके बाद आदमी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसे एक बड़ी औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। धरती में सभी को सब कुछ बैठे-बैठे मिल जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। एआई तकनीकी के दुष्प्रभाव को लेकर युवल नोआ हरारी ने अपनी किताब नेक्सस में एआई के खतरों से आगाह किया है। उन्होंने दावा किया है, पहली बार मनुष्य सभ्यता के सामने एक ऐसी मशीनी दुनिया खड़ी होने जा रही है जो मनुष्य से अधिक बुद्धिशील और पराक्रमी साबित होगी। इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक भी हो सकता है। एआई तकनीकी आने के बाद जिस तेजी के साथ मशीनें अपने आप को अपग्रेड कर लेती हैं। एक मशीन सैकड़ो और हजारों लोगों की क्षमताओं का काम अकेली कर सकती है। एआई सभी सूचनाओं, संवेदनाओं, कृत्रिम बादल और बरसात, कविता, उपन्यास, काल्पनिक कहानियां, टीवी सीरियल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े कार्य, खेती से लेकर समुद्र तक इसकी पहुंच होगी। जिस तरीके के उपकरण एआई तकनीकी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, उसके कारण सबसे बड़ा खतरा बेरोजगारी का है। मशीनों पर आश्रित होकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को ही खो देंगे। इस तरह की बात सामने आने लगी है।

एआई तकनीकी अब समाज के हर उसे क्षेत्र में घुसने के लिए तैयार खड़ी है, जहां पर अभी केवल मानव अस्तित्व ही काम करता था। अब जिस तरह के रोबोट बनाए जा रहे हैं, वह मानवों की तरह संवेदनशील और मानवों की तरह ही, वह सब कुछ कर सकते हैं, जो अभी तक मानव करते आए हैं। इस बात का भी खतरा उत्पन्न हो गया है, जो रोबोट बनाये जा रहे हैं। उसके बाद सेक्स और बच्चा पैदा करने का काम भी यही रोबोट करने लगेंगे। यह रोबोट मानवीय सभ्यता से ज्यादा संवेदनशील होंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुछ समय पहले स्मार्टफोन आया था। इस स्मार्टफोन ने लोगों की याददाश्त छीन ली। अब हर काम के लिए स्मार्टफोन की जरूरत होती है। कुछ याद नहीं रहता है, यदि स्मार्टफोन ना हो तो हम अपने परिजनों के मोबाइल नंबर और ईमेल अकाउंट का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। जब एआई का अस्तित्व अपने पूरे सवाब में आएगा, तब मनुष्य प्रजाति की कल्पना शक्ति और शारीरिक क्षमता सीमित करने का काम एआई क्रांति कर देगी। कहा जाता है, तकनीकी से डरने की जरूरत नहीं है।

तकनीकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में आती है। जिस तरह से सारे विश्व में छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़े तक स्मार्टफोन के नशे का शिकार होकर अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। एआई क्रांति के माध्यम से जिस तरह से हम संपूर्ण जीवन को मशीनों के ऊपर आश्रित करते चले जा रहे है। ऐसी स्थिति में ना तो हम शारीरिक श्रम कर पाएंगे और ना ही हम मानसिक श्रम कर पाएंगे। इस स्थिति में भविष्य का क्या होगा, आसानी से समझा जा सकता है।

तकनीकी का स्वागत किया जाना चाहिए, पर हमारे जीवन में तकनीकी का उतना ही प्रवेश होना चाहिए, जो हमारी सहायता और विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। जब करोड़ों लोगों का काम कुछ लाख मशीनें करने लगेंगी। हफ्तों और महीनो का काम पलक झपकते हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 800 करोड लोगों को पालने-पोसने, सामाजिक और पारिवारिक जीवन को किस तरह से सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जा सकेगा। तकनीकी का उपयोग करने के पहले इस पर गंभीर विचार-विमर्श करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि तकनीकी के सहारे हम विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के स्थान पर विनाश की ओर आगे बढ़ जाएं। एआई तकनीकी का उपयोग बड़े सोच-समझकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिये।

शब्द पहेली - 8651

■	1	2		■	■	3	■	4
5	■		■	6			■	
7					■	8	9	
■	■		■	10	11	■		■
12	13		14	■	15	16		
■		■	17	18	■		■	■
19		20	■	21				22
	■	23			■	■	■	
	■		■	■	24			■

बाएँ से दाएँ

1. सिंह,शेर-3
6. कृषि पैदावार-3
7. कमल सरोवर-5
8. बारीक-3
10. जरा,थोड़ा-2
12. वाराणसी-4
15. टूटना,तड़कना-4
17. शराब,मदिरा-2
19. बुद्धि,मति-3
21. सेवा,,चाकरी,देखभाल-5
23. कर्म,भाग्य-3
24. यज्ञ,होम-3

ऊपर से नीचे

2. आक्रमणकारी-5
3. समा,माहौल-3
4. आर्द्रता,नमी-3
5. चट्टान (अंग्रेजी-2)
6. अंतर,फर्क-3
9. षष्ठीपूर्ति,60 वर्ष पूरे होना-3
11. नशा,खुमार-2
13. नरम,मुलायम-3
14. एक जैसा,समान-2
16. सार-संभाल-2,3
18. अनाथ,बेसहारा-3
19. खालिस,शुद्ध-3
20. फालिज,पक्षाघात-3
22. क्रोध,खीज,गुस्सा-2

शब्द पहेली -8650 का हल

■	बे	चा	रा	■	जी	व	न	■
कि	ला	■	ई	■	न	■	भ	ला
ता	■	क	स	र	त	■	■	य
ब	द	ला	■	थ	■	ह	ल	क
■	■	का	छ	■	म	नु	■	■
म	क्का	र	■	रा	■	मा	म	ला
ही	■	■	अ	न	ब	न	■	न
ना	ग	■	द	■	हा	■	भा	त
■	म	ल	ना	■	व	च	न	■

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

27 फरवरी 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	कुंभ में	मीन	07.15 बजे से
चंद्र	मिथुन में	मेष	08.46 बजे से
मंगल	कुंभ में	वृष	10.26 बजे से
बुध	कुंभ में	मिथुन	12.24 बजे से
गुरु	मिथुन में	कर्क	14.37 बजे से
शुक्र	कुंभ में	सिंह	16.53 बजे से
शनि	मीन में	कन्या	19.05 बजे से
राहु	कुंभ में	तुला	21.16 बजे से
केतु	सिंह में	वृश्चिक	23.31 ब.से
राहुकाल		धनु	01.47 बजे से
10.30 से 12.00 बजे तक		मकर	03.52 बजे से
		कुंभ	05.38 बजे से

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
चर	05.55 से	07.23 बजे तक	रोग	05.38 से	07.1 बजे तक
लाभ	07.23 से	08.51 बजे तक	काल	07.11 से	08.43 बजे तक
अमृत	08.51 से	10.19 बजे तक	लाभ	08.43 से	10.15 बजे तक
काल	10.19 से	11.47 बजे तक	उद्वेग	10.15 से	11.47 बजे तक
शुभ	11.47 से	01.15 बजे तक	शुभ	11.47 से	01.19 बजे तक
रोग	01.15 से	02.43 बजे तक	अमृत	01.19 से	02.51 बजे तक
उद्वेग	02.43 से	04.10 बजे तक	चर	02.51 से	04.23 बजे तक
चर	04.10 से	05.38 बजे तक	रोग	04.23 से	05.55 बजे तक

शुक्रवार 2026 वर्ष का 58 वा दिन **दिशाशूल** पश्चिम **ऋतु** शिशिर। **विक्रम संवत्** 2082 **शक संवत्** 1947 **मास** फाल्गुन **पक्ष** शुक्ल **तिथि** एकादशी 22.33 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** आर्द्रा 10.49 बजे को समाप्त। **योग** आयुष्मान 19.44 बजे को समाप्त। **करण** वणिज 11.33 बजे तदनन्तर विष्टि 22.33 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 9.5 घण्टे **रवि क्रान्ति** दक्षिण 08° 25' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1872633 **जूलियन दिन** 2461098.5 **कलियुग संवत्** 5126 **कल्पारंभ संवत्** 1972949123 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885123 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1447 **महीना** रमजान **तारीख** 09 **विशेष** आमलकी एकादशी, योगेश्वर दयाल जयंती, चन्द्रशेखर आजाद शहीद दिवस।

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

न्यूज इन शॉर्ट

जिला अस्पताल में बिना टेंडर पार्किंग शुरू, वसूली पर उठे सवाल

अनूपपुर। जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल अनूपपुर में बिना टेंडर प्रक्रिया के पार्किंग व्यवस्था शुरू कर दी गई है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने अपने चहेते ठेकेदार साई मोबाईल प्लाजा को 12 हजार रुपये प्रतिमाह पर पार्किंग का काम सौंप दिया है, जबकि इस संबंध में कोई औपचारिक निविदा जारी नहीं की गई।पार्किंग स्थल पर बीते एक सप्ताह से वाहनों से प्रति दो घंटे 10 रुपये वसूले जा रहे हैं। वाहन चालकों को जो रसीद दी जा रही है, उस पर अस्पताल प्रबंधन की सील या अधिकृत उल्लेख नहीं है, जिससे वित्तीय अनियमितता और मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं।वाहन चालकों का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक मांग और बहस की स्थिति भी बन रही है। पार्किंग स्थल पर शुल्क संबंधी कोई स्पष्ट सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है।मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए तत्कालिक व्यवस्था के तहत यह निर्णय लिया गया है। सिविल सर्जन डॉ. एस.आर. परस्ते ने बताया कि फिलहाल अस्थायी रूप से रेलवे पार्किंग संचालित करने वाले ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।फिलहाल बिना टेंडर वसूली, तय राशि और ठेका प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

पं. दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान की कार्यशाला सम्पन्न

अनूपपुर।भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पार्टी जिला कार्यालय अनूपपुर में जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम की अध्यक्षता में किया गया।संभाग प्रभारी मिथिलेश पयासी ने कहा कि प्रशिक्षण महाअभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक भाव एवं विचारधारा को जागृत किया जाएगा। पंच परिवर्तन का उद्देश्य भारत को मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है, उन्होंने कहा।जिला प्रभारी संजय साहू ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करता है। उन्होंने बताया कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने के लिए जिला एवं मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम ने बताया कि जिले के सभी 16 मंडलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह महाअभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है।कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

श्रीकृष्ण सुदामा चरित्र के साथ रासलीला का हुआ समापन

सीधी। उर्मिलेश्वर धाम तिलक नगर पडरा में परम पूज्य दण्डी स्वामी निर्मायानंद सरस्वती के सानिध्य में वरिष्ठ समाजसेवी विनय कुमार सिंह परिहार के सौजन्य से आठ दिवसीय श्री राधाकृष्ण रासलीला का श्रीकृष्ण सुदामा के चरित्र के साथ भव्य समापन हुआ। लीला के समापन अवसर डां. राजेश मिश्रा सांसद सीधी, अंजू लता पटले, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर, श्रीमती बबिता करें सीएमएचओ सीधी डां. एस बी खरे विनय कुमार सिंह परिहार अखिलेश पाण्डेय ने युगल सरकार की आरती कर आशीर्वाद लिये। बुधवार को रासलीला का शुभारंभ श्रीराधाकृष्ण की निकुंज लीला से किया गया। श्री रामकृष्ण लीला प्रचार मंडल के व्यास स्वामी बृजेश शर्मा ने हरिभक्तों के पदों का गायन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात लीला में श्रीकृष्ण सुदामा चरित्र का विस्तार से मंचन किया गया। सुदामा, श्रीकृष्ण के बचपन के निर्धन मित्र थे। पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका गए और पोटली में केवल %चिउड़े% (पोहे) ले गए, जिसे कृष्ण ने बड़े प्रेम से खाया। कृष्ण ने बिन मांगे ही सुदामा की दरिद्रता दूर कर उन्हें राजसी सुख प्रदान किया। सुदामा और कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में साथ शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा अत्यंत निर्धन थे और परिवार का पालन-पोषण मुश्किल से करते थे। पत्नी के कहने पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका गए। सुदामा के फटे वस्त्र और दीनता देखकर कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने अपने आँसुओं से मित्र के चरण धोए।सुदामा संकोचवश कुछ नहीं मांग पाए, लेकिन कृष्ण ने अंतर्यामी होकर उनकी बिना कही स्थिति भांप ली। जब सुदामा घर लौटे, तो उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था। यह कृष्ण द्वारा बिना मांगे दी गई विपुल संपत्ति थी। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने निर्धन मित्र सुदामा को दो लोकों का सुख और वैभव दे कर निहाल कर दिये।उक्त रासलीला में ठाकुर जी श्रीकृष्ण की भूमिका दीपेश शर्मा, श्री जी की भूमिका गोविंद शर्मा, श्री जी की अष्ट सखियों की भूमिका में करण शर्मा, नैतिक शर्मा, रवि शर्मा, राजू शर्मा, देव कुमार शर्मा, रामवीर शर्मा ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही कान्हा जी दिगंबर शर्मा, हरीष शर्मा, छोटू मिश्रा, ऋषि मिश्रा द्वारा अभिनय किया गया।

बेटे भाग्य से और बेटियां परम सौभाग्य से लेती है जन्म- हिमाद्री

हिंदू रीति रिवाज में कन्यादान सबसे बड़ा संस्कार, वैदिक मंत्रोच्चार तथा उल्लास एवं आनंद के साथ 188 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

विजय मत, अनूपपुर

सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र हिमाद्री सिंह ने कहा है कि बेटियां ईश्वर की अनमोल रत्न होती हैं। बेटे भाग्य से और बेटियां परम सौभाग्य से जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि आज वे पुष्पराजगढ़ की पवित्र भूमि पर 188 नवदंपतियों के विवाह समारोह में सम्मिलित हो सकीं। उन्होंने कहा कि हिंदू रीति-रिवाजों में अनेक दानों का उल्लेख है, परंतु उनमें कन्यादान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्होंने बेटियों के माता-पिता को शुभकामनाएं देते हुए इस पुण्य कार्य हेतु बधाई दी। सांसद ने जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ स्थित खेल मैदान (बिजली ऑफिस परिसर) में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह को संबोधित कर रही थीं।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अत्यंत संवेदनशील है और समाज के हर वर्ग तथा प्रत्येक व्यक्ति के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है, ताकि बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक हो सके और वे सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। सांसद श्रीमती सिंह ने यह भी कहा कि जिले के जनप्रतिनिधि जिले के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

दो परिवारों को बांधने का कार्य करती है बेटियां- विधायक फुंदेलाल सिंह

विधायक पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल सिंह मार्को ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़े समाज में पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां दो परिवारों को स्नेह और संस्कार के सूत्र में जोड़ने का कार्य करती हैं। प्रत्येक माता-पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री का विवाह आनंद, उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हो, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह इसी भाव का सजीव उदाहरण है।

उन्होंने नवविवाहित वर-वधुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने जीवन में नीति, धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए परस्पर समझ, सहयोग और सम्मान के साथ जीवनयापन करें। आज का दिन नए संकल्प का दिन है। मां नर्मदा को साक्षी मानकर अपने वैवाहिक जीवन की मंगलमय शुरुआत करें तथा अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करें और परिवार के बड़ों का सम्मान करें। विधायक श्री मार्को ने कहा कि शासन का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति तक जनहितकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, और इसके लिए वे सदैव तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में ऐसे भव्य आयोजनों का संपन्न होना क्षेत्र के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह सामाजिक समरसता का अनूठा संगम- जिला पंचायत अध्यक्ष

अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह सामाजिक समरसता का अनूठा संगम है। इस आयोजन के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्ग एक सूत्र में बंधते हैं और पारस्परिक सहयोग एवं सौहार्द की भावना को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि आज जो जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, वे जीवन पर्यंत एक-दूसरे का सम्मान करें, प्रत्येक सुख-दुख में साथ निभाएं तथा आपसी सामंजस्य और विश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करें। वैवाहिक जीवन परस्पर समझ, त्याग और सहयोग पर आधारित होता है, जिसे सुदृढ़ बनाए रखना दोनों की समान जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शासन की यह जनहितकारी एवं महत्वाकांक्षी योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर नागरिक अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं।

कार्यक्रम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्चना कुमारी, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम, जनपद पंचायत अध्यक्ष पुष्पराजगढ़ मिथिलेश सिंह, पूर्व विधायक सुदामा सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित कर नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं प्रदान कीं।

सांसद एवं विधायक ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ

सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह एवं विधायक श्री फुंदेलाल मार्को सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

पारंपरिक तरीके से निकली भव्य बारात, जनप्रतिनिधि बने बाराती

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आनंद, उत्साह और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ भव्य बारात निकाली गई। आयोजन स्थल पर उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच जनप्रतिनिधि और अधिकारी बाराती बनकर शामिल हुए। सांसद हिमाद्री सिंह तथा विधायक पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल सिंह मार्को ने बारात में सहभागिता कर नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से समारोह में गरिमा और उत्साह का संचार हुआ।

188 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह के अंतर्गत आज कुल 188 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ परिणय सूत्र में बंधे। धार्मिक रीति-रिवाजों और पारंपरिक विधि-विधान के बीच संपन्न हुए इस सामूहिक विवाह समारोह में उत्साह और उल्लास का वातावरण रहा। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राही सीमा देवी, माधुरी सिंह, हंसवती, रेनू देवी तथा माया बनावल को प्रतीक स्वरूप 49 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया।

फुनगा, बदरा, मलगा चौड़ी- पौड़ी के स्वास्थ्य केन्द्रो का जिपं सीईओ ने लिया जायजा

विजय मत, अनूपपुर

व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के दिए निर्देश

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुनगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ी- पौड़ी, मलगा का निरीक्षण कर जायजा लिया गया।

भ्रमण के दौरान जनपद पंचायत के सीईओ, प्रमुख खंड चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिपं सीईओ ने भ्रमण के दौरान मरीज के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं पैथोलॉजी, दवा वितरण, सुरक्षित मातृत्व प्रसव के लिए निर्धारित पैरामीटर अनुसार व्यवस्थाओं के संबंध में सघन निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुनगा में बायो मेडिकल बेस्ट के डिस्पोजल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदरा को लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में स्थानांतरित करने, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलगा में नल जल कनेक्शन के माध्यम से व्यवस्थित पेयजल सप्लाई तथा इनवर्टर इंस्टॉलेशन आदि के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायत सीईओ ने निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों की सुविधाओं पेयजल, शौचालय तथा साफ सफाई आदि कार्य का अवलोकन करते हुए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शांति, सद्भावना, गरिमामय, भाईचारे से मिलजुल कर मनाएं आगामी सभी त्यौहार-कलेक्टर

विजय मत, अनूपपुर

जिले की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी त्यौहारों को शांतिपूर्ण, भाईचारे की भावना और हर्षोल्लास, उमंग, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर मनाया जाएगा। इस आशय की अपील कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हर्षल पंचोली की अध्यक्षता में संपन्न जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में की गई। शांति समिति की बैठक में आगामी त्यौहारों होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेटियल ड्यूटी लगाए जाने तथा विभिन्न स्थानों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नदियों के स्थानों को चिन्हित करते हुए होमगार्ड के गोताखोर, पटवारी, सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन के अमले की तैनातगी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस थाने के बल के साथ कोटवारों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने बैठक में त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख स्थानों पर आवश्यक अमले की तैनातगी तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में सर्व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

होली पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर ने नियुक्त किए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

विजय मत, अनूपपुर

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 02 मार्च को होलिका दहन, 03 मार्च को धुरेड़ी, रंगपंचमी, क्षेत्रीय फाग गीत आयोजित होंगे। उक्त त्यौहार के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए होली त्यौहार के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की है। साथ ही उन्होंने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सहयोग हेतु संबंधित नगरीय क्षेत्र के नगरपालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है।

अनूपपुर/चचाई थाना क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार अनूपपुर श्री ईश्वर प्रधान, चौकी फुनगा क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार कौशलेंद्र शंकर मिश्रा, थाना भालूमाड़ा क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार अनूपपुर मंगल दास चतुर्वेदी, जैतहरी/वेंकटनगर थाना क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार जैतहरी रमाकांत तिवारी, कोतमा थाना क्षेत्रांतर्गत प्रभारी तहसीलदार कोतमा श्री दशरथ सिंह, बिजुरी थाना क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार जैतहरी धनीराम ठाकुर, रामनगर थाना क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार अनूपपुर मिथला प्रसाद पटेल, थाना राजेन्द्रग्राम क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार पुष्पराजगढ़ लव तेंद्र सिंह, थाना अमरकंटक क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ ज्ञान दास पनिका तथा थाना करनपठार क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ श्री सोहनलाल कोल को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

एक बगिया मां के नाम तथा खेत तालाब कार्यों का जिपं सीईओ ने निरीक्षण कर लिया जायजा

विजय मत, अनूपपुर

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपाली अर्चना कुमारी ने जनपद पंचायत अनूपपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धम्मा, बदरा, चौडी- पौडी, मलगा के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री अमर साय राम जनपद सीईओ, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी मनरेगा राबेन्द्र पटेल, सहायक यंत्री रमेश पाण्डेय, उप यंत्री, हितग्राही एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच उपस्थित थे।

जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत धम्मा मैं मनरेगा अंतर्गत एक बगिया मां के नाम हितग्राही उषा सिंह पति दीपक सिंह एवं हितग्राही हेमवती पति भरत सिंह तथा खेत तालाब के हितग्राही लाल सिंह के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने एक बगिया मां के नाम हितग्राही यो को पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करने तथा समय पर खाद, पानी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एक बगिया मां के नाम योजना के माध्यम से तैयार फलदार वृक्ष के फलन से अतिरिक्त आय के स्रोत का सृजन होगा। उन्होंने खेत तालाब हितग्राहियो को निर्धारित प्रस्ताव के अनुरूप तालाब का गहरीकरण कराने के निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपाली श्रीमती अर्चना कुमारी ने ग्राम पंचायत टांका एवं चौड़ी में ग्रामीण यंत्र की सेवा द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे बहुउद्देशी भवन का निरीक्षण कर जायजा लिया गया उन्होंने निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली।

उन्होंने भवन निर्माण में गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग करने तथा भवन में पेयजल एवं विद्युतीकरण का कार्य भी समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अनियमितता

जनप्रतिनिधियों ने उठाई जांच की मांग, शासन को लाखों के नुकसान का आरोप

संविलियन भर्ती पर सवाल: आदेशों की अनदेखी, परिवीक्षा खत्म फिर भी पद पर जमे शुक्ला

विजय मत, अनूपपुर

नवगठित नगर परिषद डूमरकछार में संविलियन भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट शर्तों के बावजूद तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद भी संबंधित कर्मचारी की मूल पद पर वापसी न होने से जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में रोष व्याप्त है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार 6 फरवरी 2021 को जिला चयन समिति द्वारा ग्राम पंचायत कालीन कर्मचारियों के संविलियन का निर्णय लिया गया था। यह प्रक्रिया म.प्र. नगर पालिका सेवा (वेतन एवं भत्ता) नियम 1967 के नियम 8 के तहत की गई थी। इसी क्रम में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव रजनीश प्रसाद शुक्ला का राजस्व उपनिरीक्षक पद पर संविलियन किया गया। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि– 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी। इस अवधि में एलएसजीडी (रूस्तष्ठ) डिप्लोमा प्राप्त करना अनिवार्य होगा. डिप्लोमा प्राप्त न करने की स्थिति में मूल पद पर वापसी की जाएगी।सूत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि में एलएसजीडी डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया गया, इसके बावजूद आज दिनांक तक मूल पद पर वापसी नहीं हुई है।

संविलियन प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा 28 जून 2017 को जारी पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का संविलियन शहरी विकास विभाग में नहीं किया जा सकता। प्रदेश के अन्य नवगठित निकायों में इसी आधार पर संविलियन रोके जाने के उदाहरण भी सामने आए हैं। ऐसे में डूमरकछार में यह प्रक्रिया किन परिस्थितियों में की गई, यह जांच का विषय बन गया है।

फर्जी प्रस्ताव और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि– फर्जी प्रस्तावों एवं दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। कुछ जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों एवं फर्मों

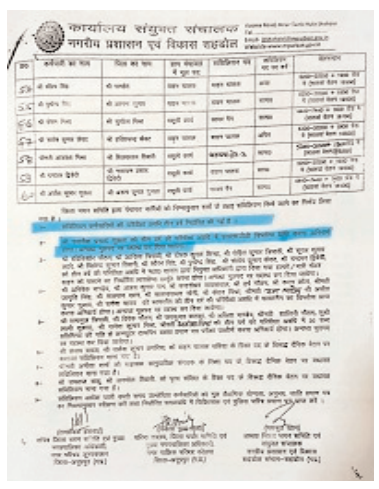

को लाभ पहुंचाया गया।नगर पालिका अधिनियम एवं लेखा-वित्त नियमों का उल्लंघन किया गया। लाखों रुपये की राशि कथित रूप से गबन की गई।

उच्च अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें भेजी गईं, लेकिन अब तक जांच प्रारंभ न होने से असंतोष बढ़ता जा रहा है।

नगर परिषद अध्यक्ष का कड़ा रुख नगर परिषद डूमरकछार के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि नियुक्ति आदेशों की शर्तों का पालन हर हाल में होना चाहिए। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि परिवीक्षा अवधि में आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं की गई है तो नियमानुसार कार्रवाई अनिवार्य है।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि परिषद की बैठकों में इस विषय को उठाया गया है और सक्षम अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र जांच प्रारंभ नहीं हुई तो परिषद स्तर पर प्रस्ताव पारित कर उच्च स्तर तक मामला ले जाया जाएगा।

न्यायालय के आदेशों की आड़?

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि उच्च न्यायालय के आदेशों की आड़ लेकर कार्रवाई टाली जा रही है। जनप्रतिनिधियों का सवाल है कि क्या न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन या अनियमितताओं की छूट दी है? यदि नहीं, तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?

समयावधि समाप्त, फिर भी पद पर कायम

परिवीक्षा अवधि समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, फिर भी संबंधित कर्मचारी पद पर कायम हैं। इससे शासन को आर्थिक नुकसान होने का आरोप लगाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वे विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।

जनता में रोष, जांच की मांग तेज

निकाय क्षेत्र में योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक न पहुंचने का आरोप भी लगाया जा रहा है। नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इस गंभीर प्रकरण पर कब संज्ञान लेता है और परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बावजूद पद पर डटे कर्मचारी के विरुद्ध क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

न्यूज इन शॉर्ट

निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का किया गया आयोजन

शहडोल। महिला बाल विकास विभाग एवं परिवहन विभाग के समन्वय से शासकीय नेहरू महाविद्यालय बुढ़ार में निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया।

पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में सहायक संचालक महिला बाल विकास श्रीमती संजीता भगत द्वारा शासकीय नेहरू महाविद्यालय बुढ़ार जिला शहडोल में निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप के माध्यम से कॉलेज में उपस्थित दूर दराज से आए हुए बालक बालिकाओं को लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया एवं ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही वाहन चालने की समझाइष दी गई। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके सुरक्षा एवं पहचान का भी आधार है। कैंप में श्रीमती नीलमणि भगत परिवहन विभाग, महाविद्यालय के डॉ0 जयशंकर सिंह, डॉ0 दिनेश वर्मा, डॉ0 अनूप कुमार सेन, श्रीमती रामकुमारी पाण्डेय पर्यवेक्षक, भानुप्रिया केसवर्कर एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

गिट्टी के अवैध परिवहन पर की गई कार्यवाही

शहडोल। जिला खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य ने जानकारी दी है कि खनिज विभाग के अमले द्वारा सिंहपुर थाना क्षेत्र मे खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की जाँच की गई। जाँच दौरान एक डम्पर एवं ट्रक को गिट्टी खनिज का परिवहन करते हुए ग्राम भमराहा में रोका गया। वाहन से गिट्टी खनिज परिवहन की कोई रॉयल्टी नहीं पायी गयी है एवं उक्त वाहन को मय खनिज के थाना सिंहपुर की अभिरक्षा में जप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

गेहूं उपार्जन हेतु पंजीयन 7 मार्च तक, अभी तक 1164 किसान पंजीकृत

शहडोल। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री विपिन पटेल ने जानकारी दी है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत समर्थन मूल्य में गेहूं उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन का कार्य 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर अपनी उपज विक्रय हेतु इच्छुक किसान निर्धारित समयावधि में निःशुल्क पंजीयन ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों एवं एमपी किसान एप पर किसान पंजीयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान सशुल्क पंजीयन एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन कर सकते है।

एनआरसी केंद्रों में भर्ती कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के उपचार की स्थिति

शहडोल। जिले के विभिन्न पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के उपचार एवं देखभाल की बेहतर ढंग से की जा रह है। एनआरसी केंद्रों में भर्ती कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, संतुलित पोषण एवं सतत देखभाल उपलब्ध कराने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही जरूरत के अनुसार संसाधनों के समुचित प्रबंधन एवं आपसी समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जिले के प्रत्येक कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को समय पर बेहतर उपचार मिल सके।

जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाए गए एनआरसी केन्द्रों की क्षमता में कुल 70 बिस्तरों की है। जिनमें से 86 बिस्तरों पर कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर समुचित उपचार एवं पोषण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

एनआरसी केंद्रों की सीईओ जिला पंचायत श्री षिवम प्रजापति द्वारा नियमित मॉनिटरिंग करने से कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चो की संख्या में लगातार बढोत्तरी हो रही है। क्षमता से अधिक बच्चो के आने पर अतिरिक्त बिस्तरो की व्यवस्था सुनिष्चित की जा रही है। जिला चिकित्सालय शहडोल स्थित एनआरसी में कुल 20 बिस्तरों में से 17 बच्चों का उपचार जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्यौहारी में निर्धारित 10 बिस्तरों के मुकाबले 15

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की प्रक्रिया अटकी

घोषणा के बाद भी जमीनी हकीकत शून्य, 100-100 सीटर बालक-बालिका केंद्रों की घोषणा के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रगति धीमी

विजय मत, शहडोल

प्रदेश सरकार द्वारा संभाग स्तर पर 100-100 सीटर बालक एवं बालिका परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा को काफी समय बीत चुका है, लेकिन शहडोल सहित कई संभागों में यह योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जनजातीय युवाओं को जिस सशक्त शैक्षणिक आधार की उम्मीद थी, वह फिलहाल केवल कागज़ों तक सीमित नजर आ रही है।

विभागीय समन्वय की कमी बनी बाधा

योजना का क्रियान्वयन जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से किया जाना है, किंतु विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि समस्त कार्यवाही भोपाल स्तर से होनी है, जिसके चलते जिला स्तर पर कोई ठोस प्रगति संभव नहीं हो पा रही। स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में पूरी योजना प्रशासनिक उलझनों में फंसी हुई है।

स्वीकृति के बावजूद नहीं दिखी तैयारी

शहडोल के लिए एक 100 सीटर प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत होने की जानकारी दी गई है, परंतु अब तक भवन चयन, बजट आवंटन, अधोसंरचना विकास और शिक्षकों की नियुक्ति जैसी बुनियादी प्रक्रियाएं प्रारंभ नहीं हो सकी हैं। स्वीकृति और क्रियान्वयन के बीच की यह दूरी युवाओं के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों पर बढ़ता बोझ

आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विद्यार्थी पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें बड़े शहरों में महंगी कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ता है। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र से उन्हें स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार हो रही देरी ने उनकी योजनाओं को प्रभावित किया है।

समयसीमा अस्पष्ट, असंतोष गहराया

योजना के क्रियान्वयन की कोई स्पष्ट समयसीमा तय नहीं होने से युवाओं और अभिभावकों में असंतोष बढ़ रहा है। बार-बार की घोषणाओं और धीमी प्रशासनिक प्रक्रिया ने इस महत्वाकांक्षी पहल की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर यह योजना कब तक वास्तविक रूप ले पाएगी।

भालू के हमलों में तीन लोगों की हो चुकी मौत, वन विभाग अलर्ट मोड पर

विजय मत, शहडोल

जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र के जंगलों में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। बीते माह दो अलग-अलग वन परिक्षेत्रों में भालू के हमलों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से दो घटनाएं केशवाही वन परिक्षेत्र में हुई थीं। इन दर्दनाक घटनाओं के बाद विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क करने और सुरक्षा उपायों की जानकारी देने का अभियान तेज कर दिया है।

वन विभाग की टीम इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों को जंगल में प्रवेश के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में समझा रही है। विशेष रूप से महुआ बीनने और तेंदूपत्ता संग्रह करने जाने वाले ग्रामीणों को समूह में जाने, सुबह-शाम अकेले जंगल में न जाने, शोर करते हुए चलने और जंगली जानवर दिखने पर उकसाने से बचने की सलाह दी जा रही है। विभाग द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि भालू आमतौर पर अचानक सामने आने पर हमला करता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

केशवाही वन परिक्षेत्र के रेंजर अंकुर तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के जंगलों में भालुओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हाल ही में हुए हमलों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता और महुआ सीजन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगलों में जाते हैं, ऐसे में जोखिम और बढ़ जाता है। इसलिए पहले से ही लोगों को बचाव के तरीके समझाए जा रहे हैं।

वन विभाग की टीम ग्रामीण अंचलों में बैठकें कर रही है और लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी जंगली जानवर की गतिविधि दिखने पर तुरंत वन अमले को सूचना दें। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सावधानी बरतते हुए जंगल में प्रवेश करें, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

बाइक पेड़ से टकराने पर ब्यौहारी उप जेल के प्रहरी की दर्दनाक मौत

विजय मत, शहडोल

जिले के ब्यौहारी उप जेल में पदस्थ एक जेल प्रहरी की गुरुवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब प्रहरी ड्यूटी के लिए घर से निकले थे और रास्ते में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उनकी जान चली गई।

पुलिस के अनुसार मृतक प्रहरी की पहचान 29 वर्षीय अभिषेक सिंह के रूप में हुई है, जो उप जेल ब्यौहारी में पदस्थ थे। गुरुवार तड़के उनकी सुबह की शिफ्ट थी। वे अपने कमरे से बाइक लेकर ड्यूटी के लिए निकले थे। इसी दौरान ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यायालय के सामने उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जा भिड़ी।

हादसे में अभिषेक सिंह के सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने घायल अवस्था में उन्हें देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अभिषेक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया।

घटना की जानकारी मिलते ही उप जेल ब्यौहारी के अधिकारी और कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। साथी कर्मचारी अपने सहकर्मी की असमय मौत से स्तब्ध नजर आए। अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाया गया है।

पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसा सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।युवा प्रहरी की अचानक मौत से विभाग में शोक का माहौल है।

विधानसभा में गूंजी शहडोल एआरटीओ की करतूत

नियम विरुद्ध विदेश यात्रा, भ्रष्टाचार व कदाचार के आरोपों पर घिरीं अनपा खान

विजय मत, शहडोल

शहडोल की एआरटीओ अनपा खान का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में अनुपपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री बिसाह लाल सिंह द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सदन में जानकारी दी कि 31 जनवरी 2026 तक एआरटीओ के विरुद्ध स्वेच्छाचारिता, मनमानी, अनैतिक कृत्य, भ्रष्टाचार तथा कूट रचना से संबंधित चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच वर्तमान में प्रचलन में है।

बिना अनुमति विदेश यात्रा पर हुआ था निलंबन

मंत्री ने बताया कि भोपाल में पदस्थापना के दौरान 21 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक बिना अवकाश स्वीकृति एवं बिना शासन की अनुमति के विदेश यात्रा पर जाने के कारण 14 सितंबर 2023 को उन्हें निलंबित किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी गईं।

कमिश्नर ने भी जताई नाराज़गी

सूत्रों के अनुसार शहडोल संभाग की कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने भी एआरटीओ की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए शासन एवं परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। प्रशासनिक हलकों में इसे गंभीर माना जा रहा है।

बस संचालकों में नाराज़गी

स्थानीय बस संचालकों का आरोप है कि वर्तमान कार्यकाल में कथित रूप से पूर्व आरटीओ की तुलना में कई गुना अधिक अवैध वसूली की जा रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से परेशान हैं। कुछ संचालकों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि विभागीय दबाव और कार्रवाई के भय से खुलकर सामने वे नहीं आ पा रहे हैं।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

पोस्टिंग को लेकर भी चर्चा

शहर में यह भी चर्चा है कि एआरटीओ की पदस्थापना को लेकर भारी लेनदेन हुआ था और अब उसकी भरपाई स्थानीय स्तर पर की जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष से इस संबंध में स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

विधानसभा में मामला उठने और प्रशासनिक स्तर पर नाराज़गी सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें चल रही जांच और शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जांच में गंभीर आरोप सिद्ध होते हैं तो आने वाले दिनों में मामला और तूल पकड़ सकता है।

पेपर बिगड़ जाने से आहत आईटीआई छात्र ने फांसी लगाकर दे दी जान

विजय मत, शहडोल

जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोलुहा चौकीटोला में एक 25 वर्षीय आईटीआई छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पेपर बिगड़ जाने से आहत छात्र ने गुरुवार सुबह घर के पीछे बाड़ी में आम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनोज चौधरी, पिता नत्थूलाल चौधरी, आईटीआई का छात्र था। उसका एक विषय में बैक लगा हुआ था, जिसका पेपर देने वह बुधवार को शहडोल गया था। शाम को घर लौटने पर उसने अपने बड़े भाई अनिल चौधरी को बताया कि उसका पेपर ठीक नहीं गया और वह इसे लेकर काफी परेशान है। भाई ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि दोबारा परीक्षा दे देना, लेकिन मनोज गुमसुम रहा। बताया जा रहा है कि उसने बुधवार रात खाना भी नहीं खाया और चुपचाप अपने कमरे में सो गया।

गुरुवार सुबह वह रोज की तरह उठकर मवेशियों को बांधने के लिए खलिहान की ओर गया। जब उसका बड़ा भाई बाड़ी की तरफ पहुंचा तो देखा कि मनोज आम के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। उसने शोर मचाया तो परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना जैतपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पेपर बिगड़ जाने से आहत होकर उसने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

प्रदर्शन

शासकीय हॉस्टलों की अनियमितताओं एवं व्यवस्थागत खमियों का भी मुद्दा उठाया गया

दीक्षांत समारोह में घटिया भोजन के विरोध में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

विजय मत, शहडोल

जिले के शासकीय छात्रावासों में कथित अनियमितताओं एवं पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को बासी व दुर्गंधयुक्त भोजन परोसे जाने के विरोध में एनएसयूआई शहडोल इकाई ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी के नेतृत्व में सौंपा गया।ज्ञापन में एनएसयूआई ने शासकीय हॉस्टलों में व्यवस्थागत खामियों, छात्रों की सुरक्षा तथा हाल ही में छात्र सुमित चौधरी की मृत्यु की घटना को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

प्रमुख मांगें छात्र सुमित चौधरी की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच एनएसयूआई ने मांग की है कि घटना की निष्पक्ष, गहन एवं उच्च स्तरीय जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा विशेष जांच दलसे कराई जाए। दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई तथा जांच प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है, ताकि छात्रों और अभिभावकों का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।

दीक्षांत समारोह में भोजन व्यवस्था पर कार्रवाई संगठन ने आरोप लगाया कि दीक्षांत समारोह जैसे गरिमामय अवसर पर छात्रों को घटिया एवं दुर्गंधयुक्त भोजन परोसा गया, जबकि वीआईपी अतिथियों के लिए भव्य व्यवस्थाएं की गईं। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग, प्रत्येक छात्रावास में अनुभवी एवं जिम्मेदार वार्डन की नियुक्ति, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे,छात्रावास के आसपास नियमित पुलिस गश्त

स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाएं

परिसर में स्थायी प्राथमिक चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन की नियमित जांच स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था

एनएसयूआई ने कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

ज्ञापन सौंपते समय युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष आशीष तिवारी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी, जिला उपाध्यक्ष आशीष द्विवेदी, सिमरन कौर, शुभम सोधियां, ब्लॉक अध्यक्ष अमन तिवारी, आईटी सेल अध्यक्ष महेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मुख्य नपा अधिकारी ने प्रगतिरत विकास कार्यों का किया निरीक्षण

विजय मत, शहडोल

मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती आषा भंडारी ने शहडोल नगरपालिका अंतर्गत किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों, उपयंत्रियों एवं ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कोटमा में प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड का अवलोकन किया। बस स्टैंड निर्माण की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्य में अपेक्षित तेजी लाने तथा सभी तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहडोल के वार्ड क्रमांक 2 में प्रस्तावित सामुदायिक भवन स्थल का निरीक्षण किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि सामुदायिक भवन स्थानीय नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सुविधा मिलेगी। साथ ही सीएमओ ने वार्ड क्रमांक 1 स्थित संजीवनी क्लीनिक, पुराना नगर पालिका कार्यालय से पुलिस लाइन ग्राउंड के आगे तक सीसी रोड निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया एवं सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देष संबंधित एजेंसी को दिए गए।

टी20 विश्व कप सुपर-8 में आज इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगी न्यूजीलैंड

कोलंबो, एजेंसी

श्रीलंका के खिलाफ जीत से उत्साहित न्यूजीलैंड की टीम शुक्रवार को यहां टी20 विश्वकप क्रिकेट के सुपर-8 मैच में इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगी। कीवी टीम के स्पिनरों ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और वह यही सिलसिला इंग्लैंड के खिलाफ भी जारी रखना चाहेगी। कीवी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर काफी अच्छे फार्म में हैं जिसका लाभ भी टीम को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम पहले ही अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गयी है और उसका लक्ष्य इस मैच में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल के लिए लय बनाये रखना रहेगा। कप्तान हैरी ब्रूक के अलावा उसके उन्य बल्लेबाज पिछले सुपर-8 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ असफल रहे थे। ऐसे में वे अपना फार्म हासिल करना चाहेंगे।

दूसरी ओर श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत के बाद न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफी अच्छा प्लस 3.050 हो गया है। ऐसे में इस मैच में जीत के साथ वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी पर अगर वह मामुली अंतर से हारती भी है तो भी उसकी सेमीफाइनल की संभावनांए बनी रहेंगी। वहीं इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान का नेट रन रेट माइनस 0.461 हो गया है। ऐसे में पाक टीम नेट रन रेट में तभी आगे निकल सकती है जब न्यूजीलैंड को मैच में बड़ी हार मिले। न्यूजीलैंड की टीम जिस प्रकार श्रीलंका के खिलाफ छह स्पिनरों के साथ सहजता से उतरी थी उससे तय है कि इस मैच में भी वह उसी टीम के साथ उतरेगी।

इस मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनरों और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला होना तय है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और ऑलराउंडर विल जैक्स दोनों ने ही पाक स्पिनरों साइम अयूब, मोहम्मद नवाज और शादाब खान के सामने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और उनका लक्ष्य कीवी टीम के खिलाफ इसी प्रदर्शन को बनाये रखना रहेगा हालांकि ये इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि कीवी स्पिनर मिचेल सैंटनर, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स और कोल मैककॉन्ची प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर कहर ढ़ा सकते हैं। ब्रूक अच्छी फॉर्म में हैं पर अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर का फार्म में नहीं होना इंग्लैंड के लिए चिन्ताजनक है। टीम को अपने गेंदबाजों विल जैक्स और लियाम डॉसन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। प्रेमदासा की पिच पर अगर स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हों तो 165 से 175 रन भी काफी अच्छे माने जाएंगे।रविंद्र ने कहा, इस तरह के मुकाबले में खेलने के लिए हमेशा ही आत्मविश्वास बनाये रखना होता है क्योंकि हमें अंदाजा है कि पिच कैसी होगी पर मुझे लगता है कि किसी भी समय इंग्लैंड को कम करके आंकना गलती होगी।

विरोध टीम काफी अच्छी है। उनके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके पास बल्लेबाजी क्रम में विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं। साथ ही कहा कि टी20 प्रारुप में कुछ भी हो सकता है जो टीम मैच के दिन अच्छा खेलेगी जीत उसकी की होगी।

शाम 7 बजे से होगा मुकाबला

दोनो ही टीमें इस प्रकार है

इंग्लैंड : हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, फिल साल्ट (विकेटकीपर), बेन डकेट, सैम करेन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग, लाइक वुड

न्यूजीलैंड : मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, कोल मैककॉन्ची, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, रचिन रविंद्र, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, इश सोढ़ी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ अधिक प्रयोग से बचे भारतीय टीम पोंटिंग

सिडनी । ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले सुपर-8 मुकाबले को देखते हुए एक अहम सलाह दी है। पोंटिंग का कहना है कि इस मैच में भारतीय टीम को अधिक बदलाव नहीं करते हुए वहीं अंतिम ग्यारह उतारनी चाहिये जो अबतक तक खेलती आई है। पोंटिंग के अनुसार अधिक प्रयोग कि रणनीत नुकसानेह साबित हो सकती है। इस पूर्व कप्तान के अनुसार बड़े टूर्नामेंट में स्थिरता और संतुलन से ही जीत मिलती है।

इससे पहले भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में अपना संयोजन बदला था जिससे उसे काफी नुकसान हुआ था। उस मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम में बाएं हाथ के अधिक बल्लेबाजी होने के कारण उपकप्तान अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को अवसर दिया था पर ये प्रयोग विफल रहा। उस मैच में सुंदर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनो में ही विफल रहे थे।

ज्वेरेव हुए अलटफेर के शिकार केकमानोविच ने तीन सेटों में हराया

अकापुल्को,एजेंसी

सर्बिया के मियोमिर केकमानोविच ने जर्मनी के टेनिस स्टारा अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर एक बड़ उलटफेर करते हुए मेक्सिकनो टेलसेल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर-फाइनल में प्रवेश किया है। केकमानोविच ने तीन सेट के रोमांचक मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त ज्वेरेव के खिलाफ 6-3, 6-7(3), 7-6(4) से ये जीत दर्ज की । इस मुकाबले में केमानोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन कर विरोधी खिलाड़ी को कोई अवसर नहीं दिया। । मैच के बाद केकमानोविच ने कहा, जीत से वह खुश है पिछले कुछ साल उनके लिए कठिन रहे हैं। इसलिए उन्हें इस बातक की खुशी है कि इस मैच में सब कुछ उनके अनुसार हुआ। वह विशेष अवसर पर आक्रामक रहे जिसका भी लाभ उन्हें मिला। वहीं अनुभवी ज्वेरेव निरंरतता के लिए संघर्ष करते दिखे। उन्होंने 17 गलतियां कीं, जबकि केकमानोविच ने छह गलतियां कीं। इस जीत के साथ ही केकमानोविच ने ज्वेरेव के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 2-2 से बराबर कर लिया और एटीपी 500 इवेंट के आखिरी आठ में पहुंच गए हैं। यहां उनका मुकाबला फ्रांस के टेरेंस एटमाने से होगा, एटमाने ने एक अन्य मुकाबले में राफेल जोडार को 6-2, 4-6, 6-1 से हराया था।

सेमीफाइनल से अब कौन सी टीम बाहर होगी

अहमदाबाद । टी20 विश्वकप सुपर-8 से अब तक एक टीम श्रीलंका बाहर हो गयी है। उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब एक और टीम का बाहर होना तय है। ये मुकाबला मैच ग्रुप-1 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम के प्रशंसक वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की जीत चाहेंगे क्योंकि इससे भारतीय टीम के सेमीफाइनल की उम्मीदें बनी रहेंगी।

दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज, दोनों का रनरेट बहुत अच्छा है। ऐसे में इस मुकाबले की विजेता टीम के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का अच्छा अवसर है।

द हंड्रेड से पाक खिलाड़ियों को बाहर नहीं किया जाएगा : ईसीबी

लंदन, एजेंसी

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा है कि द हंड्रेड क्रिकेट लीग से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर नहीं किया जाएगा। ईसीबी के अनुसार इस प्रकार की जो भी आशंकाएं लगायी गयी हैं। वे सही नहीं हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लीग में आईपीएल से जुड़ी फ्रैंचाइजियां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी। द हंड्रेड की 4 फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जिनका मालिकाना अधिकार भारतीयों के पास है औये पाक खिलाड़ियों को नहीं लेगी। वहीं अब ईसीबी और द हंड्रेड की 8 फ्रेंचाइजियों की तरफ से संयुक्त बयान जारी किया गया है कि द हंड्रेड में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और अगर कोई टीम ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

इस सप्ताह एक रिपोर्ट में कहा गया गया था कि आईपीएल टीमों के मालिकों से जुड़ीं 4 फ्रेंचाइजी मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स (आरपीएसजी ग्रुप), एमआई लंदन (रिलायंस), सदर्न ब्रेव (जीएमआर) और सनराइजर्स लीड्स (सन ग्रुप) द हंड्रेड की नीलामी के लिए पंजीकृत पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाये रख सकती हैं।गौरतलब है कि साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद से ही विदेशी लीग में आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजियों में पाकिस्तानी क्रिकेटर बहुत ही कम नजर आये हैं। हालांकि भारतीयों के द हंड्रेड की फ्रेंचाइजियों को खरीदने से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में बहुत कम रुचि दिखा रहे थे। पिछले साल के टूर्नामेंट में सिर्फ 2 पाक खिलाड़ी खेलत दिखे थे। इतना ही नहीं, द हंड्रेड के अब तक हुए सभी 5 सीजन में कुल मिलाकर 9 पाकिस्तानी खिलाड़ी ही दिखे हैं। फ्रेंचाइजी के नए मालिक इस सीजन से कामकाज संभालेंगे।

ईसीबी और द हंड्रेड की फ्रेंचाइजियों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है, लीग को नए दर्शकों तक पहुंचने, क्रिकेट के खेल के विकास और हर किसी को हमारे खेल से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस लीग में खिलाड़ियों को राष्ट्रीयता के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए।बयान में आगे कहा गया है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय में वापसी करने को तैयार हरमनप्रीत

होबर्ट । भारतीय महिला क्रि केट टीम शुरुवार को यहां दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ वापसी करने उतरेगी। भारतीय टीम को पहले एकदिवसीय में 6 विके से हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में मेजबान टीम तीन मैचों की इस सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम के लिए राहत की बात ये है कि कप्तान हरमनप्रीत कौर भी फिट हो गयी हैं। हरमनप्रीत को पहले एकदिवसीय में चोट लग गयी थी। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा है कि हरमनप्रीत अब ठीक है और खेलने जा रही हैं। पहले एकदिवसीय में बल्लेबाजी के दौरान घुटने में चोट लगने से हरमनप्रीत मैदान पर नहीं लौट पाई थीं, जिससे टीम की चिंताएं बढ़ गई थीं। कहा गया है कि हरमनप्रीत को बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी और मेडिकल स्टाफ उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है। कप्तान के नहीं होने से उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने टीम की कमान संभाली। वहीं अब अब कप्तान की वापसी से प्रबंधन को भी राहत मिली है।
पहले मुकाबले में भारतीय टीम 48.3 ओवर में 214 रन ही बना पायी थी।

विनीसियस के गोल से रियाल मैड्रिड बेनफिका को हराकर अंतिम 16 में पहुंची

मैड्रिड , एजेंसी

विनीसियस जूनियर के गोल से रियाल मैड्रिड की टीम बेनफिका को 2-1 से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंच गयी है। दूसरे चरण के इस मुकाबले में रियाल जीत के साथ ही अब 3-1 से आगे हो गयी है। उसने पहला चरण भी 1-0 से जीता था। दूसरे चरण में बेनफिका की ओर से 14वें मिनट में राफा सिल्वा ने गोल कर मुकाबला 1-1 से बराबरी पर ला दिया। वहीं दो मिनट बाद ही ऑरेलियन चोउमेनी ने एक गोल कर रियाल को बढ़त दिला दी। मैच के 80वें मिनट में विनीसियस जूनियर ने एक गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। वहीं एक अन्य मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने मोनाको को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनायी। दोनों टीमों के बीच दूसरा चरण 2-2 से बराबरी पर रहा, हालांकि पहले चरण में मिली बढ़त से पीएसजी को लाभ हुआ। एक अन्य मुकाबले में इटली की अटलांटा ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को दूसरे चरण में 4-1 से हराया।

व्यापार

सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 82,249 बंद, निफ्टी में 14 अंकों की तेजी रही

मुंबई ,एजेंसी

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को मिला-जुला कारोबार हुआ। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद भी मुनाफावसूली हावी होने के कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 27.46 अंक टूटकर 82,248.61 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 14 .05 अंक की हल्की बढ़त के साथ 25,496.55 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान डिफेंस और हेल्थकेयर शेयरों से बाजार को सहारा मिला। निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.48 फीसदी और निफ्टी हेल्थकेयर 1.24 फीसदी बढ़कर की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा 1.08 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.95 फीसदी, निफ्टी ऑयलएंडगैस 0.87 फीसदी, निफ्टी ऑटो 0.80 फीसदी, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 0.78 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.39 फीसदी और निफ्टी इन्फ्रा 0.32 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ।

निफ्टी मीडिया 0.68 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी 0.16 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.11 फीसदी और निफ्टी सर्विसेज 0.06 फीसदी की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

आज लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मिला-जुला कारोबार हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 392.05 अंक की तेजी के साथ 59,798.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स एक अंक की हल्की कमजोरी के साथ 17,117.65 पर था।

सेंसेक्स पैक के शेयरों में बीईएल, अदाणी पोर्ट्स, सनफार्मा, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, एसबीआई, टीसीएस, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, टाइटन और टेक महिंद्रा के शेयर लाभ में रहे। ट्रेंट, पावरग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, टीएंडटी, एचसीएल टेक और एमएंडएम के शेयर नुकसान में रहे।

वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार बढ़त के साथ खुले। सुबह बीएसई सेंसेक्स 82,418 के स्तर पर खुला। वहीं इसी तरह ?निफ्टी 50 ने भी 25,556 के स्तर पर शुरुआत की। शुरुआती मिनटों में यह 30.15 अंक की बढ़त लेकर 25,512.65 पर कारोबार करता दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद निवेशक फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं। बीच-बीच में मुनाफावसूली भी देखी जा रही है, जिससे बढ़त सीमित बनी हुई है।

फिल्म निर्माण की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे

नई दिल्ली । प्रख्यात फिल्मकार शेखर कपूर का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आने वाले समय में फिल्म निर्माण की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में आयोजित बीएस मंथन कार्यक्रम में एआई के दौर में सिनेमा विषय पर उन्होंने कहा कि भविष्य में फिल्में केवल निर्देशक की सोच तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि दर्शक और एआई मिलकर कहानी रचेंगे। मासूम, मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी चर्चित फिल्मों के निर्देशक कपूर ने कहा कि एआई फिल्मकारों को सशक्त बनाएगी। उनका कहना था कि जहां पारंपरिक तरीके से एक फिल्म बनाने में उन्हें लगभग तीन साल लगते हैं, वहीं एआई की मदद से सीमित संसाधनों में भी दो दिन के भीतर फिल्म बनाई जा सकती है। इससे उन रचनाकारों को अवसर मिलेगा, जिनके पास बड़े बजट या संसाधन नहीं हैं।

हर साल हो रही हैं 303 करोड़ घरेलू यात्राएं पर्यटकों के लिए कम पड़ रहे हैं होटल

नई दिल्ली, एजेंसी

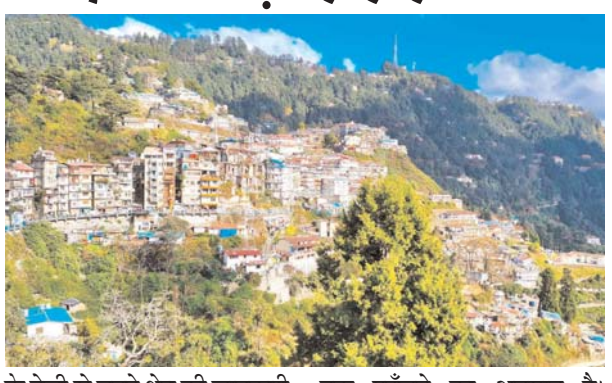

भारत में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और यह अब केवल सेक्टर नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। विदेशी और घरेलू दोनों तरह के पर्यटन में वृद्धि हो रही है, जिससे होटलों की मांग बढ़ रही है और उनकी कीमतें भी महंगी होती जा रही हैं। वर्तमान में पर्यटन उद्योग का भारत के जीडीपी में योगदान 5 फीसदी है, जबकि 2047 तक यह 10 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। इसी अवधि में केवल पर्यटन इंडस्ट्री में 200 मिलियन रोजगार मिलने की संभावना है। दिल्ली के द्वारका में आयोजित एसएटीटीई 2026 में 60 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक और 3200 से अधिक ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। इस साल की थीम थी एन ओर्व्च्यु निटी काल इंडिया आयोजन में अजीत बजाज, अध्यक्ष, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पद्मश्री पुरस्कार विजेता ने पर्यटन के तेजी से बढ़ते क्षेत्र की जानकारी दी। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत आने वाले समय में वैश्विक पर्यटन का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा।

इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के एक अधिकारी के अनुसार भारत का पर्यटन क्षेत्र 'ट्रिपल इंजन ग्रोथ' पर बढ़ रहा है। घरेलू, आउटबाउंड और इनबाउंड। हर साल देश में 303 करोड़ से अधिक घरेलू यात्राएं हो रही हैं, और भारतीयों का विदेश यात्रा खर्च 42 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। अनुभव आधारित, आध्यात्मिक और क्षेत्रीय पर्यटन के कारण टियर-2 और टियर-3 शहरों में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि भारत का पर्यटन केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों में निहित है। यात्रियों को आज अनुभव और जुड़ाव चाहिए ।

और भारत इसे सबसे बेहतर रूप में प्रदान करता है। 2027 तक भारत का ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर 125 अरब डॉलर के घरेलू बाजार की ओर बढ़ रहा है।

सरकारी खर्च से पावर सेक्टर में तेजी, निजी उद्योग अब भी ज्यादा सुस्त

नई दिल्ली । देश में पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) की रफ्तार इस समय दो अलग तस्वीरें पेश कर रही है। एक ओर पावर ट्रांसमिशन से जुड़ी हाई वोल्टेज कंपनियां रिकॉर्ड प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं गैर-विद्युत औद्योगिक कंपनियों की चाल अब भी धीमी बनी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों के नए ऑर्डर में सालाना आधार पर 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री 39 प्रतिशत बढ़ी है। इन कंपनियों का मुनाफा मार्जिन बढ़कर 20.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष से 5.4 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने 2022 से 2032 के बीच ट्रांसमिशन क्षेत्र में 9.15 लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना बनाई है। इसके तहत 8 से 10 बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। तीन कॉरिडोर के लिए उपकरणों का काम पहले ही तय हो चुका है। अनुमान है कि 2027 से नए ऑर्डर में और तेजी आएगी तथा 2030 तक मांग मजबूत बनी रह सकती है। बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है, जो पहले के अनुमान से 12 प्रतिशत अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार फैक्ट्रियों की क्षमता उपयोग दर 77.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

सोने का भाव 600 से ज्यादा टूटा

नई दिल्ली । कीमती धातुओं के वायदा बाजार में गुरुवार को सुस्ती का माहौल देखने को मिला। घरेलू स्तर पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना और चांदी दोनों गिरावट के साथ खुले और कारोबार के दौरान भी दबाव में रहे। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 615 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछला बंद भाव 1,61,145 रुपये था। इस समय यह 468 रुपये की नरमी के साथ 1,60,677 रुपये पर कारोबार कर रहा था। सत्र के दौरान सोने ने 1,60,745 रुपये का उच्च और 1,60,516 रुपये का निचला स्तर छुआ।

रिपोर्ट - बेरोजगारी दर 2025 में 4.5 से घटकर 2026 में 4.1 प्रतिशत रहने की संभावना

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी की उम्मीद : आईएमएफ

वाशिंगटन,एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 2026 तक का आकलन पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2026 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 2.4 प्रतिशत बढ़ सकता है, जो 2025 के 2.2 प्रतिशत से अधिक है। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मोटे तौर पर सकारात्मक बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बेरोजगारी दर 2025 के अंत में 4.5 प्रतिशत से घटकर 2026 में 4.1 प्रतिशत रह सकती है। आईएमएफ ने कहा कि रोजगार बाजार में अत्यधिक गिरावट न आए तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दर में और कटौती से बचना चाहिए।

महंगाई दर 2027 तक अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत के लक्ष्य तक आ सकती है। फेडरल रिजर्व की मौजूदा रेपो दर 3.6 प्रतिशत है, जिसे घटाकर लगभग 3.4 प्रतिशत किया जा सकता है। 2025 में नीतिगत ब्याज दर में तीन बार कटौती की गई थी। आईएमएफ ने अमेरिकी संघीय सरकार के बढ़ते कर्ज पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक कर्ज जीडीपी के अनुपात में 2025 के लगभग 100 प्रतिशत से बढ़कर 2031 तक 110 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यह आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात शुल्क नहीं होते, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। संरक्षणवादी नीतियां अपेक्षा से अधिक नकारात्मक असर डाल सकती हैं। हालांकि, अमेरिका को मजबूत उत्पादकता वृद्धि का लाभ मिला है। आईएमएफ के अनुसार, अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2026 में बढ़ेगी, बेरोजगारी घटेगी और महंगाई नियंत्रित रहेगी, लेकिन बढ़ता सरकारी कर्ज और संरक्षणवादी नीतियां आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम बन सकती हैं।

सागर जिले के गढ़ाकोटा में आयोजित 218वें रहस मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री

हर खेत को मिलेगा पानी, एक लाख करोड़ के बजट से संवरेगा मप्र का किसान : मोहन

विजय मत, ब्यूरो गढ़ाकोटा/सागर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के रहली क्षेत्र को कृषि आधारित औद्योगिक गतिविधियों का नया केंद्र बनाने की घोषणा करते हुए यहां फूड पार्क स्थापित करने का ऐलान किया। गढ़ाकोटा के ऐतिहासिक रहस मेले के शुभारंभ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की धरती पर उद्योग, कृषि और परंपरा का संगम होगा। फूड पार्क की स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों को बेहतर बाजार और क्षेत्र को आर्थिक गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने रहस मेले के 217 वर्ष पुराने इतिहास का स्मरण करते हुए आल्हा-ऊदल की वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की पहचान केवल शौर्य से नहीं, बल्कि परिश्रम और आत्मसम्मान से भी है। बड़े लड़ैया महोबा वाले की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने वीरभूमि को कोटिशः प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऋतुओं और मेलों का गहरा संबंध है– फसल कटाई के साथ पर्व और उत्सव जीवन में उमंग भरते हैं। डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। कृषि आधारित व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। रहली क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से दलहन, तिलहन और अन्य फसलों को स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन का अवसर मिलेगा। इससे परिवहन लागत घटेगी और उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बजट 2026-27 में नई यशोदा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता जारी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कार्यक्रम में क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया और नर्मदा को सोनार नदी से जोड़ने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधनों के समुचित उपयोग और सिंचाई विस्तार के लिए राज्य सरकार गंभीर है। सोनार नदी के माध्यम से सिंचाई रकबा बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में बीड़ी उद्योग और तेंदूपत्ता संग्रहण लाखों परिवारों की जीविका का आधार रहे हैं। रहली में सूक्ष्म औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए समिति गठित की जाएगी। बीड़ी निर्माण, तेंदूपत्ता प्रसंस्करण और हस्तशिल्प आधारित इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से उन्नयन योजना बनाई जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जनवरी माह (फरवरी 2026 में देय) की राशि सिंगल क्लिक से 32.78 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 196.72 करोड़ रुपए अंतरित किए। प्रत्येक हितग्राही को प्रतिमाह 600 रुपए की सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है।

आधारभूत ढांचे को मजबूती

मुख्यमंत्री ने खेजरा-शाहपुर-मोकलपुर फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति दी। रहली और गढ़ाकोटा कृषि उपज मंडी के उन्नयन के लिए 5-5 करोड़ रुपए तथा शाहपुर उपमंडी के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। रहली-रमखरिया-सिमरिया नायक बहेरिया मढ़ी मार्ग (लगभग 22 किमी) के उन्नयन और चौड़ीकरण का भी ऐलान किया गया। गढ़ाकोटा और रहली में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। ढाना के शासकीय महाविद्यालय में वाणिज्य और इतिहास संकाय प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सांदीपनि विद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें और साइकिलें प्रदान की जा रही हैं, जबकि स्कूल टॉपर को स्कूटी दी जाती है।

औद्योगिक और सांस्कृतिक समन्वय

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास केवल आर्थिक योजनाओं से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से भी जुड़ा है। रहस मेला केवल परंपरा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पहचान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, कृषि, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम में सांसद राहुल लोधी, सागर सांसद लता वानखेड़े, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप लारिया, बृज बिहारी पटेरिया, शैलेन्द्र जैन, वीरेन्द्र सिंह लोधी, उमादेवी खटीक, महापौर संगीता सुशील तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, रंजीता गौरव पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए सरकार संकल्पित है और रहली-गढ़ाकोटा क्षेत्र को कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। फूड पार्क की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचना हमारी सरकार का दायित्व ही नहीं संकल्प है: मंत्री उइके

विजय मत, भोपाल

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, विशेष रूप से जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मिशन की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन-संधारण व्यवस्था तथा ग्रीष्मकालीन तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने समिति के सदस्यों को विभागीय प्रगति की जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन परिणामोन्मुख और पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुल 111.34 लाख ग्रामीण परिवारों में से 82.19 लाख परिवारों, अर्थात 73.84 प्रतिशत घरों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इन परिवारों को प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो रहा है। प्रदेश के 24,893 ग्रामों को शत-प्रतिशत नल कनेक्शन प्रदान कर ÷हर घर जल÷ ग्राम घोषित किया गया है। इनमें से 17,146 ग्रामों को ग्राम सभाओं द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, जो सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त उदाहरण है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि बुरहानपुर जिला को भारत सरकार द्वारा देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला घोषित किया गया।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृहखंडवा ने ड्राई ऐश निष्पादन का स्थापित नया कीर्तिमान: मंत्री तोमर

विजय मत, भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के खंडवा जिले में स्थापित श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह ने कुल 210 बल्कर ट्रक ड्राई निजी कंपनियों को भेजकर ड्राई ऐश निष्पादन का नया रिकार्ड कायम किया। विद्युत गृह की 600 मेगावाट क्षमता की दो एवं 660 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयों से उत्पन्न ड्राई ऐश को प्रभावी प्रबंधन करते हुए कुल 210 बल्कर ट्रक के माध्यम से 7793 मीट्रिक टन ड्राई ऐश निष्पादित की गई। यह मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की फ्लाई ऐश के सदुपयोग,रि-साईकिल व निबटारा करने की प्रतिबद्धता का परिचायक है।पर्यावरण संबंधी बढ़ती चिंता और समस्या की बढ़ती गंभीरता के कारण फ्लाई ड्राई ऐश का प्रबंधन करना अनिवार्य हो गया है। पॉवर प्लांट के फेज-1 से 143 बल्कर ट्रक द्वारा 5229 मीट्रिक टन ड्राई ऐश निष्पादित की गई जो कि पिछले वर्ष में निष्पादित 131 बल्कर ट्रक की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार फेज-2 से 67 बल्कर ट्रक द्वारा 2563 मीट्रिक टन ड्राई ऐश सफलतापूर्वक निष्पादित की गई। ड्राई ऐश ताप विद्युत गृहों में कोयले के दहन से उत्पन्न उप-उत्पाद है, जिसका उपयोग निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

एमपी ने लगातार दूसरे वर्ष एसएटीटीई 2026 में जीता 'बेस्ट स्टेट टूरिज्म' अवॉर्ड

विजय मत, भोपाल। मध्यप्रदेश को दक्षिण एशिया के प्रमुख ट्रैवल एवं टूरिज्म प्रदर्शनी एसएटीटीई 2026 में प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। लगातार दूसरे वर्ष यह सम्मान प्राप्त कर राज्य ने भारत के प्रमुख और पसंदीदा पर्यटन स्थलों में अपनी मजबूत पहचान को और सुदृढ़ किया है। पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एसएटीटीई अवॉर्ड्स समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जिसे मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने प्राप्त किया। विजेताओं का चयन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और उद्योग जगत के वरिष्ठ नेताओं की जूरी द्वारा किया गया। सचिव पर्यटन एवं मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलैया राजा टी. ने बताया कि एसएटीटीई 2026 में लगातार दूसरे वर्ष 'बेस्ट स्टेट टूरिज्म' अवॉर्ड मिलना मध्यप्रदेश के पर्यटन इको सिस्टम को मजबूत करने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ सतत, जिम्मेदार और अनुभव-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार निरंतर प्रयासरत है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सीता शुक्ला द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप, 11 प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-01, एमपी नगर, भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं ई.एम.एस. 21 इंडस टाउन, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सीता शुक्ला। प्रधान संपादक- विजय शुक्ला
(*समाचार चयन के लिए पी.आरर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार)। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र शहडोल होगा। आर.एन.आई. क्रमांक- MPHIN/2015/66998, e-mail: vijaymat.sdl@gmail.com। मोबाइल- +91 88899 77997